



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1988/ फाल्गुन 15, 1909

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1988/PHALGUNA 15, 1909

इस भाग में भिन्न एवं संख्या वाली जाती है जिससे इक पट्ट पर अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part, in order that it may be filed as a  
separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के द्वारा द्वारा जारी किए गए रायितोंधार आदेश और अधिसंचानाएँ  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than  
the Ministry of Defence)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1988

का.आ. 438 :—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6  
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रमोद दलाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को  
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के  
लिए दिया है कि उसे सम्पूर्ण भारत वर्ष में व्यवसाय करने  
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी  
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन  
के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(7)/88-न्या.

आर.एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICE

New Delhi, the 27th January, 1988

SO 438—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Promod Dalal, Advocate, Bombay for appointment as a Notary to practise in whole of India

2 Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice

[No F 5(7)/88-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

आधिकार

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1987

का. आ. 439.—आधिकार अधिनियम, 1961  
1931 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड खण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 6-5-1986 की अधिसूचना सं. 6697 का. सं. 398/10/86 आ. क. (ब) का अविसंधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार इतद्वारा उक्त अधिनियम, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के राजस्व अधिकारी ओ एम एल. सरीन को कर-बसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हेतु प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना ओ एम एल. सरीन द्वारा कर-बसूली अधिकारी के रूप में कार्ड-भार प्रहण करते की तारीख से सागू होगी।

[मे. 7670 (का. सं. 398/9/87 आ. क. (ब))  
श्री ई अलेक्जेंडर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
(INCOME-TAX)

New Delhi, the 30th December, 1987

S.O. 439.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6697 [F. No. 398/10/86-IT(B) dated the 6-5-86, the Central Government hereby authorises Shri M. L. Sarin, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. L. Sarin takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7670/F. No. 398/9/87 IT(B)]  
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1988

स्टाम्प

का. आ. 440.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रवत्त क्षमियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इतद्वारा उस शुल्क को माफी करती है जो नेशनल को-ऑपरेटिव ऐचलपर्सेंट कारपोरेशन, द्वारा इकाइय करोड़ रुपये के मूल्य के 11 प्रतिशत एन. सी. डी. सी. बंध-पत्र 2003 (चौबीसवीं श्रृंखला) के रूप में उत्सवित प्रामिसरी नोटों के स्वदृष्टि में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[स. 3/88-स्टाम्प का. सं. 33/7/88-बि०क०]

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1988

STAMPS

S.O. 440.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the duty with which the bonds in the nature of Pro-missory notes described as 11 per cent NCDC Bonds 2003 (XXIV th) Series to the value of rupees fifty one crores only to be issued by National Co-operative Development Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 3/88-Stamp. F. No. 33/7/88-ST]

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1988

स्टाम्प

का. आ. 441—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त क्षमियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो पाथर फाइब्रेन्स कारपोरेशन द्वारा मात्र एक सी करोड़ रुपये के मूल्य के 9 प्रतिशत कर मुक्त पी एफ. सी बंधपत्र (प्रथम श्रृंखला) के रूप में उत्सवित प्रूफपत्रों के स्वदृष्टि में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[स. 4/88—स्टाम्प का. 33/56/87-बि०क०]]  
बी०आर० मेहमी अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1988

STAMPS

S.O. 441.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the duty with which the bonds in the nature of debentures described as 9 per cent Tax free PFC Bonds (First Series) to the value of rupees one hundred crores only to be issued by the Power Finance Corporation are chargeable under the said Act.

[No 4/88-Stamp-F. No. 33/56/87-ST]  
B. R. MEHMI, Under Secy.

(ग्रामीण कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी 1988

का. आ. 442—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त क्षमियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इतद्वारा श्री के राजगोपालन को प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30-9-87 से ग्रामीण बैंक 30-9-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके द्वारा श्री राजगोपालन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगे।

[संख्या एफ 2-33/87-ग्राम आर. बी]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th January, 1988

S.O. 442.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. Rajgopalan as the Chairman of the Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank and specifies the period commencing on the 30-9-87 and ending with the 30-9-90 as the period for which the said Shri Rajgopalan shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-33/87-RRB]

का. आ. 443—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री कृष्ण बिहुरी लाल वास को समस्तीयुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समस्तीयुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-11-1987 से प्रारंभ होकर 30-11-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री दास अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ 2—49/87 भारत ग्रामीण]

S.O. 443.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Krishna Biharilal Das as the Chairman of the Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur and specifies the period commencing on the 1-11-87 and ending with the 30-11-90 as the period for which the said Shri Das shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-49/87-RRB]

का. आ. 444—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री एच वी मल्लाया को वरदा ग्रामीण बैंक, कुम्टा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-10-1987 से प्रारंभ होकर 31-10-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री मल्लाया अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-38/87-भारत ग्रामीण]

S.O. 444.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri H. V. Mallya as the Chairman of the Varada Gramene Bank, Kumta and specifies the period commencing on the 31-10-1987 and ending with the 31-10-90 as the period for which the said Shri Mallya hold office as Chairman.

[No. F. 2-38/87-RRB]

का. आ. 445—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री एल. वी. रेडी को रायालसीमा ग्रामीण

बैंक, कुडुपा (आ.प्र.) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-9-87 से प्रारंभ होकर 30-9-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री रेडी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ 2—37/87 भारत ग्रामीण]

S.O. 445.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri L. B. Reddy as the Chairman of the Rayalaseema Gramenea Bank, Cuddapah (A.P.) and specifies the period commencing on the 1-9-87 and ending with the 30-9-90 as the period for which the said Shri Reddy shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-37/87-RRB]

का. आ. 446—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री आर. एन. शाह को फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उ.प्र.) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30-9-87 से प्रारंभ होकर, 30-9-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री शाह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ 2/19/87 भारत ग्रामीण]

S.O. 446.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. N. Shah as the Chairman of the Faizabad Kshetriya Gramin Bank, Faizabad (U.P.) and specifies the period commencing on the 30-9-87 and ending with the 30-9-90 as the period for which the said Shri Shah shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-19/87-RRB]

का. आ. 447—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री आर. ए. बस्तोंदकर को वलसाड औ गेस ग्रामीण बैंक, वलसाड गुजरात का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 10-9-87 से प्रारंभ होकर 30-9-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री दस्तोंदकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2—4/87—भारत ग्रामीण]

S.O. 447.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. A. Bastodkar as the Chairman of the Valsad-Dangs Gramin Bank, Valsad (Gujarat) and specifies the period commencing on the 10-9-87 and ending with the 30-9-90 as the period for which the said Shri Bastodkar shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-4/87-RRB]

का. आ. 448.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बौ.सौ. जैन को श्रीगंगानगर क्षत्रीय ग्रामीण बैंक श्रीगंगानगर का अध्यक्ष नियुक्त करता है तथा 1-11-87 से प्रारम्भ होकर 30-11-90 को समाप्त होने वाला अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान श्री जैन अध्यक्ष के रूप में काय करें।

[संख्या एफ. 2-9/87-मार. भार. बौ.]

S.O. 448.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri B. C. Jain as the Chairman of the Sri Gangangagar Kshetriya Gramin Bank, Sri Gangangagar and specifies the period commencing on the 1-11-87 and ending with the 30-11-90 as the period for which the said Shri Jain shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-9/87-RRB]

का. आ. 449.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम. राममूर्ति को श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है तथा 4-11-1987 से प्रारम्भ होकर 30-11-1990 को समाप्त होने वालो अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान श्री राममूर्ति अध्यक्ष के रूप में काय करें।

[संख्या एफ. 2-57/87-मार. भार. बी.]

S.O. 449.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri M. Ramamurthy as the Chairman of the Sree Anantha Gramenee Bank, Ananthapur and specifies the period commencing on the 4-11-1987 and ending with the 30-11-1990 as the period for which the said Shri Ramamurthy shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-57/87-RRB]

का. आ. 450.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एल.एन. विश्वनाथन को चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना का अध्यक्ष नियुक्त करता है तथा 2-11-1987 से प्रारम्भ होकर 30-11-1990 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान श्री विश्वनाथन अध्यक्ष के रूप में काय करें।

[संख्या एफ. 2-3/87-मार. भार. बी.]

प्रबोध कुमार तेजयान, अवर सचिव

S.O. 450.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri L. N. Vishwanathan as the Chairman of the Chambal Kshetriya Gramin Bank, Morena and specifies the period commencing on the 2-11-1987 and ending with the 30-11-1990 as the period for which the said Shri Vishwanathan shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-3/87-RRB]

P. K. TEIJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

का. आ. 451.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के बंड (३.) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक थी एस.एस. नाडकर्णी को 13 नवम्बर, 1987 से आरम्भ होने वाली और 18 सितम्बर, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के वास्ते निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ. 7/1/88-बी.ओ.-I]

New Delhi, the 29th January, 1988

S.O. 451.—In pursuance of the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri S. S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay, as a director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a further period beginning 13th November, 1987 and ending 18th September, 1988.

[No. F. 7/1/88-BO. I]

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1988

का. आ. 452.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फार्म "क" के माथ संलग्न टिप्पणी (ब) के उपबंध निम्नलिखित बैंकों पर जहां तक उनका संबंध 31 दिसम्बर, 1987 को उनके तुलनपत्रों से है, लागू नहीं होगे—

1. इलाहाबाद बैंक

2. बैना बैंक

3. यूनाइटेड बैंस्ट्रन बैंक लिमिटेड

[सं. 15/2/88-बी.ओ. III]

प्राण नाथ, अवर सचिव

New Delhi, the 9th February, 1988

S.O. 452.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks, viz:

(i) Allahabad Bank;

(ii) Dena Bank;

(iii) United Western Bank Ltd.

in respect of their balance sheet as at the 31st December, 1987.

[No. 15/2/88-BO. III]  
PRAN NATH, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)  
नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1988

का. आ. 453.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में मीजे वाये तहसील पेण/जिला रायगढ़ के रावे तहसील पेण, जिला रायगढ़, तक पैट्रोलियम तेल अथवा नैसिंग गैस अथवा एफाल्यूथंट अथवा अन्य खनिज पदार्थों के परिवहन के लिये पाईप लाईन, “इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस क्रकर काम्प्लेक्स विभाग, विलेपाले (प) मुंबई द्वारा बिलाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त समितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

गवर्नर के उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस क्रकर काम्प्लेक्स, नागोठणा, तहसील रोहा, जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह आहता है कि उसकी सुनवा ई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफेत।

अनुसूची

पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम, 1962 की धारा (3) की उपधारा (1) अधिसूचना क्रमांक तारीख - - 1988 की अनुसूची

गांव का नाम	तहसील	जिला	सर्वों नंबर	हिस्सा नं.	गट नंबर	छेद
1	2	3	4	5	6	7
उंडडे	पेण	रायगढ़	228	3 पी	0-07-0	
			236	0 पा	0-07-5	
			242	0 पी	0-02-0	
धोंडपाडा	पेण	रायगढ़	33	1 पी	0-15-6	
			29	2 पी	0-03-8	
			26	3 पी	0-01-0	
			26	6 पी	0-00-3	
			26	10 पी	0-03-2	
			26	9 पी	0-06-1	
कोप्रोली	पेण	रायगढ़	41	5 पी	0-00-5	
			41	3 पी	0-14-9	
			41	4 पी	0-08-1	
			41	2 पी	0-5-8	
			41	1 पी	0-10-9	
			203	23 पी	0-01-0	
			203	24 पी	0-01-7	
			44	1 पी	0-02-7	
			44	2 पी	0-00-5	
			49	4 पी	0-05-0	
			49	1 पी	0-12-0	

1	2	3	4	5	6
			53	8 पी	0-03-0
			53	7 पी	0-00-5
			53	2 पी	0-01-8
			52	1 पी	0-02-3
			51	5-6 पी	0-12-4
			51	3 पी	0-01-6
			51	1 पी	0-03-0
			63	5 पी	0-00-5
			63	7 पी	0-00-5
			62	4 पी	0-07-5
			161	38 पी	0-13-3
			161	2 पी	0-04-3
			161	1 पी	0-02-5
			160	2 पी	0-05-1
			157	8 पी	0-02-7
			157	7 पी	0-4-5
			171	2(1) पी	0-0-5
			153	0 पी	0-1-7
			133	0 पी	0-1-5
			116	2 पी	0-1-5
			95	0 पी	0-2-5
			201	0 पी	0-1-5
			44	4 पी	0-0-2
			44	3 पी	0-0-2
			44	5 पी	0-10-5
			45	1 पी	0-2-0
			50	3 पी	0-1-5

[सं. 39027/1/87-पी सी-III(i)]

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

New Delhi, the 12th February, 1988

S.O. 453.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum, oil, natural gas, effluent or any mineral from village Wave, Tal. Pen, District Raigad to village Rave, Taluka Pen District Raigad in the State of Maharashtra, Pipelines should be laid through the agency of Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division Vile Parle (W), Bombay;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby notify their intention to acquire the right of user in the lands referred to in the schedule;

Any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said lands may prefer an objection within 21 days from the date of the notification, to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Nagothane, Tahsil Roha, District Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Schedule to Notification under Section 3(1) of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962

Name of Village	Tahsil	District	Surey No.	Hissa No.	Gat No.	Area
1	2	3	4	5	6	7
Umbrade	Pen	Raigad	228	3(P)		0-07-0
			236	0(P)		0-07-05
			242	0(P)		0-02-0
Dhondpada	Pen	Raigad	33	1(P)		0-15-6
			29	2(P)		0-03-8
			26	3 P		0-01-0
			26	6 (p)		0-00-3
			26	10(P)		0-03-2
			26	9(P)		0-06-1
Koproli	Pen	Raigad	41	5(p)		0-5-5
			41	3((p)		0-14-9
			41	4(p)		0-9-1
			41	2(p)		0-5-8
			41	1(p)		0-10-9
			203	23(p)		0-1-0
			203	24(p)		0-1-7
			44	1(p)		0-2-7
			44	2(p)		0-0-5
			49	4(p)		0-3-0
			49	1(p)		0-12-6
			53	8(p)		0-3-0
			53	7(p)		0-0-5
			53	2(p)		0-1-8
			52	1(p)		0-2-3
			51	5-6(p)		0-12-4
			51	3(p)		0-1-6
			51	1(p)		0-2-0
			63	5(p)		0-0-5
			63	7(p)		0-0-5
			62	4(p)		0-7-5
			161	38(p)		0-13-3
			161	2(p)		0-4-3
			161	1(p)		0-2-5
			160	2(p)		0-5-1
			157	8(p)		0-2-7
			157	7(p)		0-4-5
			171	2(1)(p)		0-0-5
			153	0(p)		0-1-7
			133	0(p)		0-1-5
			116	2(p)		0-1-5
			95	0(p)		0-2-5
			201	0(p)		0-1-5
			44	4(p)		0-0-2
			44	3(p)		0-0-2
			44	5(p)		0-10-5
			45	1(p)		0-2-0
			50	3(p)		0-1-5

का आ. 454.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में मोर्जे साईंड तहसील पनवेल, जिला रायगढ़ से गव्हाण तहसील-पनवेल, जिला रायगढ़ तक पट्रोलियम तेल अथवा नेसिंग गैस अथवा एफट्यूअंट अथवा अन्य खनिज पदार्थों के परिवहन के लिये पाईप लाईन, इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस के कर काम्पलेक्स विमांग, विलेपासे (प) मुंबई द्वारा बिलाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिलाने के प्रयोजन के लिये एतद् पावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की व्यापारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अन्ना अधिकार एतद्वारा घोषित किया है।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई अद्वितीय हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

### अनुसूची

पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की व्यापारा (3) की उपधारा (1)

गांव का नाम	तहसील	जिला	सब्हों नंबर	हिस्सा नंबर	गंट नंबर	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	हे. आर.
साईंड	पनवेल	रायगढ़	256	2 पी	—	0-04-5
			256	5 पी		0-00-2
			248	4 पी		0-00-7
			253	3 पी		0-03-5
			253	5 पी		0-04-3
			260	3 पी		0-05-5
			260	8 पी		0-05-3
			261	1 पी		0-00-5
			261	2 पी		0-11-9
			261	7 पी		0-00-2
			263	1 पी		0-06-8
			263	3 पी		0-03-0
			263	2 पी		0-02-0
			265	3 पी		0-00-3
			265	10 पी		0-12-5
			265	14 पी		0-00-5
			264	5 पी		0-11-6
गव्हाण	पनवेल	रायगढ़	65	6 पी		0-02-8
			65	12 पी		0-01-8
			70	5 पी		0-00-5
			72	1 पी		0-08-3

1	2	3	4	5	6
		84	3 अ पी		0-01-7
		65	1 पी		0-00-8
		88अ	10 पी		0-03-5
		88 अ	6 पी		0-01-0
		88 अ	5 पी		0-01-5
		361	7 पी		0-03-7
		273	2 पी		0-01-8
		274	6 पी		0-00-5
		274	2 पी		0-00-7
		279	3 पी		0-00-2
		279	9 पी		0-01-1
		279	4 पी		0-02-5
		279	5 पी		0-01-0
		279	6 पी		0-00-2
		287	3 + 4 + 5 पी		0-01-8
दिघाटी	पनवेल	रायगढ़	30	1 पी	0-18-7
		6क	7 पी		0-04-2
		6 क	6ब पी		0-02-0
		86	1 पी		0-12-1
		86	3 पी		0-03-0
		83	1 पी		0-08-3
		85	10 पी		0-18-3
		85	4 पी		0-04-0
		85	16 पी		0-05-0
		77	0 पी		0-06-0
		81	0 पी		0-04-0
		82	3 पी		0-08-8
		82	2 पी		0-05-8
		82	1 पी		0-07-0

[सं. 34027/1/87-पी सी-III(ii)]

S.O. 454.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum, oil, Natural gas, effluent or any mineral from village Sai, Tal. Panvel District Raigad to village Gavhan, Tal. Panvel District Raigad in the State of Maharashtra, Pipelines should be laid through the agency of Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division Vile Parle (W), Bombay;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of use in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i), Section 3 of the Petroleum and Minerals

363 GT/88-2.

Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby notify their intention to acquire the right of user in the lands referred to in the schedule;

Any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said lands may prefer an objection within 21 days from the date of the notification, to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Nagothane, Tahsil Roha, District Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner

## SCHEDULE

Schedule to Notification under Section 3 (1) of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962

Name of Village	Tahsil	District	Survey No.	Hissa No.	Gat. No.	Area
						H. R.
Sai	Panvel	Raigad	256	2(p)		0-04-5
			256	5(P)		0-00-2
			248	4(P)		0-00-7
			253	3(P)		0-03-5
			253	5(P)		0-04-3
			260	3(P)		0-05-3
			260	8(P)		0-05-3
			261	1(P)		0-00-5
			261	2(P)		0-11-9
			261	7(P)		0-00-2
			263	1(P)		0-06-8
			263	3(P)		0-03-0
			263	2(P)		0-02-0
			265	3(P)		0-00-3
			265	10(P)		0-12-5
			265	14(P)		0-00-5
			264	5(P)		0-11-6
Gavhan	Panvel	Raigad	65	6(P)		0-02-8
			65	12(P)		0-01-8
			70	5(P)		0-05-5
			72	1(P)		0-08-3
			84	3A(P)		0-01-7
			65	1(P)		0-00-8
			88A	10(P)		0-03-5
			88A	6(P)		0-01-0
			88A	5(P)		0-01-5
			361	7(P)		0-03-7
			273	2(P)		0-01-8
			274	6(P)		0-00-5
			274	2(P)		0-00-7
			279	3(P)		0-00-2
			279	9(P)		0-01-1
			279	4(P)		0-02-5
			279	5(P)		0-01-0
			279	6(P)		0-00-2
			287	3+4 5(p)		0-01-8
Dighati	Panvel	Raigad	30	1(P)		0-18-7
			6(C)	7(P)		0-04-2
			6(C)	6B(P)		0-02-0
			86	1(P)		0-12-1
			86	3(P)		0-03-0
			83	1(P)		0-08-3
			85	10(P)		0-18-3
			85	4(P)		0-04-0
			85	16(P)		0-05-0
			77	0(P)		0-06-0
			81	0(P)		0-04-0
			82	3(P)		0-08-08
			82	2(P)		0-05-08
			82	1(P)		0-07-0

[No. 34027/1/87-PC-III (ii)]

का.आ. 455.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है की महाराष्ट्र राज्य में मोजेवापोली तहसील अलिबाग जिला रायगढ़ में आगरसूरे तहसील अलिबाग, जिला रायगढ़ तक पेट्रोलियम तेल अथवा जैसांगिक गैस अथवा एफल्यूअंट अथवा अन्य खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए पाइप लाइन, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कापोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र गैम फ्रेंकर कॉम्प्लेक्स विभाग, विलेपालैं (प) मुबई द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जि करते का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आधेप सक्षम प्राधिकारी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉपोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र गैस फ्रेंकर कॉम्प्लेक्स, नागोठणा, तहसील रोना जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आधेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई अविकाश हो या किसी विद्युत्यवस्थाएँ की मार्फत।

#### अनुसूची

पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा (3) की उपधारा (1) अधिसूचना क्रमाक्रमांक तारीख 1988 की अनुसूची

गाव का नाम	तहसील	जिला	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र
मुरेत	अलिबाग	रायगढ़	60	1 पी		0-8-5
			60	2 पी		0-1-0
			60	3 पी		0-4-2
			63	2 पी		0-4-0
			61	1 पी		0-4-6
			61	3 पी		0-2-2
			61	4 पी		0-10-6
			44	2 पी		0-17-7
			46	0 पी		0-15-1
			47	2 पी		0-5-0
			87	0 पी		0-2-0
			86	0 पी		0-23-7
			32	8 पी		0-1-5
			32	12 पी		0-0-2
			32	11 पी		0-13-9
			31	0 पी		0-3-7
			21	0 पी		0-5-8
			24	2 पी		0-4-0
			24	4 पी		0-33-3
			13	0 पी		0-3-8
सातिर्जे	अलिबाग	रायगढ़	107	1ब (पी)		0-03-3
			105	0(पी)		0-06-0
			102	0 (पी)		0-09-6
			95	0(पी)		0-00-5
			94	1इ(पी)		0-00-5
झिराड	अलिबाग	रायगढ़	522	पी		0-07-4

S.O. 455.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum, oil, natural gas, effluent or any mineral from village Wagholi, Tal. Alibag, District Raigad to village Agarsure, Tal. Alibag, District Raigad in the State of Maharashtra, Pipelines should be laid through the agency of India Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Vile Parle (W), Bombay.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby notify their intention to acquire the right of user in the lands referred to in the schedule:

Any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said lands may prefer an objection within 21 days from the date of the notification, to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Nagothane, Tahsil Roha, District Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

### SCHEDULE

#### Schedule to Notification under Section 3(1) of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962

Name of Village	Tahsil	District	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area H.R
Mushet	Alibag	Raigad	60	1(P)		0-08-5
			60	2(P)		0-01-0
			60	3(P)		0-04-2
			63	2(P)		0-04-0
			61	1(P)		0-04-6
			61	3(P)		0-02-2
			61	4(P)		0-10-6
			44	2(P)		0-17-7
			46	0(P)		0-15-1
			47	2(P)		0-05-0
			87	0(P)		0-02-0
			86	0(P)		0-23-7
			32	8(P)		0-01-5
			32	12(P)		0-00-2
			32	11(P)		0-13-9
			31	0(P)		0-03-7
			21	0(P)		0-05-8
			24	2(P)		0-04-0
			24	4(P)		0-33-3
			13	0(P)		0-03-8
Satirje	Alibagh	Raigad	107	1B(P)		0-3-3
			105	0(P)		0-6-0
			102	0(P)		0-9-6
			95	0(P)		0-0-5
			94	1E 1(P)		0-0-5
Zirad	Alibag	Raigad	.	522(P)		0-7-4

[No. 34027/1/87-PC-III (iii)]

का आ. 456.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है की महाराष्ट्र राज्य में मीजे खिरनेर तहसील—उरण जिला रामगढ़ से जासई तहसील—उरण, जिला रायगढ़ तक पेट्रोलियम तेल अथवा नैसर्गिक गैस अथवा एफ्लूयंट अथवा अन्य खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए पाइप लाइन, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस एकर कॉम्पलेक्स विभाग, विलेपार्ले (प) मुंबई द्वारा बिल्ड जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विधान के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुमति में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वाएँ केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करन का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में हिनबदू कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र गैस क्रेकर कॉम्पलेक्स, नारंगाठांडा, तहसील रोडा जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से २१ दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह आहता है की उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा (3) की उपधारा (3) अधिसूचना अमाक तारीख 1988 की अनुसूची

गाव का नाम	तहसील	जिला	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
जिरनेर	उरण	रायगढ़	72	2 अपी		0-01-0
			70	3 पी		0-00-2
			73	2 पी		0-00-2
			80	1 पी		0-01-7
			80	2 + 4 पी		0-03-0
			80	3 पी		0-04-1
			78	1 पी		0-03-8
भोम	उरण	रायगढ़	18	1क (2) पी		0-04-6
जियली-भोम	उरण	रायगढ़	10	0पी		0-00-3
			16	1पी		0-05-0
			16	2 पी		0-04-9
			16	3पी		0-09-6
			17	2 पी		0-06-1
विधाण	उरण	रायगढ़	239	3 पी	--	0-05-0
			239	2पी		0-05-3
			237	7 पी		0-02-5
			237	5पी		0-03-4
			237	4पी		0-06-3
			237	6 पी		0-03-0
			237	3 पी		0-01-8
			237	2पी		0-03-2
			236	5पी		0-00-5
			41	0 पी		0-01-2
कंठवली	उरण	रायगढ़	30	2 ब पी	--	0-00-2
			30	3 ब पी		0-01-3
			30	3 अ पी		0-02-3
			29	8 पी		0-02-5
			29	5 पी		0-01-0
			1	5 पी		0-00-2
			39	1ब (3)पी		0-06-0
			39	1ब (2)पी		0-01-0

1	2	3	4	5	6	7
बोलोडाखार	उरण	रायगढ़	74	10	पी	0-01-0
			77	8	पी	0-03-1
			77	1	पी	0-01-0
			75	13	पी	0-00-8
			75	12	पी	0-00-3
			72	9	पी	0-00-2
			72	6	पी	0-00-8
			72	3	पी	0-01-7
			68	13	पी	0-00-5
			18	6+9	पी	0-04-7
			21	6	पी	0-00-5
			19	13	पी	0-00-5
			43	10	पी	0-00-8
			43	4	पी	0-01-7
			35	5	पी	0-00-8
			42	14	पी	0-03-0
			41	9	पी	0-02-0
			41	8	पी	0-02-8
			41	6	पी	0-01-0
			41	5	पी	0-00-2
			39	5	पी	0-01-0
			40	6	पी	0-00-5
			40	5	पी	0-01-3
			40	1	पी	0-06-0
चिले	उरण	रायगढ़	40	2अ	पी	0-04-5
			40	2ब	पी	0-03-0
			40	1	पी	0-02-2
			40	5	पी	0-11-8
			40	4	पी	0-07-3
			41	5	पी	0-09-6
			32	2+2अ+4	पी	0-05-6
			33	2	पी	0-11-6
			26	1	पी	0-00-8
			26	4	पी	0-03-2
			26	5	पी	0-06-7
			20	6	पी	0-00-7
			20	7	पी	0-03-0
			20	4	पी	0-01-0
			20	2	पी	0-07-2
			28	5	पी	0-02-0
			21	5	पी	0-00-3
			8	4	पी	0-01-2
			8	58	पी	0-09-6
जामई	उरण	रायगढ़	137	8	पी	0-04-5
			137	9	पी	0-12-6
			137	10	पी	0-01-5
			138	10अ	पी	0-00-5

1	2	3	4	5	6	7
जासई-जारी	उरण	गायगढ़	138	2 + 7 + 11 धीपी	0-00-7	
			138	4 पी	0-01-2	
			138	5 बा	0-04-6	
			140	6 पी	0-03-3	
			140	5 पी	0-33-8	
			140	2 पी	0-05-6	
			140	1 पी	0-00-7	
			152	7 ब	0-13-4	
			152	7 अ पी	0-04-5	
			152	5 पी	0-00-2	
			154	9 पी	0-11-3	
			154	8 पी	0-00-2	
			154	7 पी	0-03-7	
			154	5 पी	0-13-4	
			155	34 + अ पी	0-12-0	
			157	1 पी	0-01-0	
			158	2 पी	0-03-1	
			164	4 पी	0-03-4	
			164	2 पी	0-02-7	
			58	1 पी	0-01-5	
			60	5 पी	0-01-5	
			68	6 पी	0-02-3	
			60	4 ब	0-01-5	
			67	5 पी	0-01-0	

[म. 34027/1/87 पी सी III (iv)]

पम्. के गुप्ता, डेस्क अधिकारी

S.O. 456.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum, oil, natural gas, effluent or any mineral from village Chirner, Tal. Uran District Raigad to village Jassai, Tah. Uran District Raigad in the State of Maharashtra, Pipelines should be laid through the agency of Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division Vile Parle (W), Bombay;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby notify their intention to acquire the right of user in the lands referred to in the schedule;

Any person interested in the said lands having any objection for laying the pipelines through the said lands may prefer an objection within 21 days from the date of the notification, to the Competent Authority, Indian Petrochemicals Corporation Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Nagothane, Tahsil Roha, District Raigad.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner

#### SCHEDULE

Schedule to Notification under Section 3(1) of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962,

Name of Village	Tahsil	District	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area
						H. R.
Chirner	Uran	Raigad	72	2A(P)		0-01-0
			70	3(P)		0-00-2
			73	2(P)		0-00-2
			80	1 (P)		0-01-7
			80	2 + 4(P)		0-03-0

1	2	3	4	5	6	7
Bhom	Uran	Raigad	80 78 18	3(P) 1(P) 1C(2) (P)	0-04-1 0-03-8 0-04-6	
Chikhali-Bhom	Uran	Raigad	10 16 16 16 17	0 (P) 1(P) 2(P) 3(P) 2(P)	0-00-3 0-05-0 0-04-9 0-09-6 0-06-1	
Vindhane	Uran	Raigad	239 239 237 237 237 237 237 237 237 236 41	3(P) 2(P) 7(P) 5(P) 4(P) 6(P) 3(P) 2(P) 5(P) 0 (P)	0-05-0 0-05-3 0-02-5 0-03-4 0-06-3 0-03-0 0-01-8 0-03-2 0-00-5 0-01-2	
Kanthavali	Uran	Raigad	30 30 30 29 29 1 39 39	2B (P) 38 (P) 3A (P) 8(P) 5(P) 5D (P) 1B (3) (P) 1B (2) (P,	0-00-2 0 01-3 0-02-3 0 02-5 0 01-0 0 00-2 0 06-0 0 01-0	
Belondakhar	Uran	Raigad	74 77 77 75 75 72 72 72 68 18 21 19 43 43 35 42 41 41 41 41 39 40 40 40	10(P) 8(P) 1 (P) 13(P) 12(P) 9 (P) 6 (P) 3 (P) 13 (P) 6+9 (P) 6 (P) 3(P) 10 (P) 4 (P) 5 (P) 14 (P) 9 (P) 8 (P) 6 (P) 5 (P) 5 (P) 6 (P) 1 (P)	0 01-0 0 03-1 0 01-0 0 00-8 0 00-3 0 00-2 0-00-8 0-01-7 0-00-5 0-04-7 0-00-5 0-00-5 0-00-8 0-01-7 0-00-8 0-03-0 0-02-0 0-02-8 0-01-0 0-00-2 0-01-0 0-00-5 0-01-3 0-06-0	

1	2	3	4	5	6
Chirle	Uran	Raigad	40	2A (P)	0-04-5
			40	2B (P.)	0-03-0
			40	1(P)	0-02-2
			40	5 (P)	0-11-8
			41	4(P)	0-07-3
			41	5(P)	0-09-6
			32	2 + 3A +	0-05-6
				4 (P)	
			33	2 (P)	0-11-6
			26	1 (P)	0-00-8
			26	4 (P)	0-03-2
			26	5 (P)	0-5-7
			20	6 (P)	0-00-7
			20	7 (P)	0-03-0
			20	4 (P)	0-01-0
			20	7 (P)	0-07-2
			20	5 (P)	0-02-0
			21	5 (P)	0-00-3
			8	4(P)	0-01-?
			8	5 + 8 (P)	0-09-6
Jasai	Uran	Raigad	137	8 (P)	0-04-5
			137	9 (P)	0-12-6
			137	10 (P)	0-01-5
			138	10A (P)	0-00-5
			138	2 + 7 + 11B(P)	0-00-7
			138	4 (P)	0-01-2
			138	5B(P)	0-04-6
			140	6 (P)	0-03-3
			140	5 (P)	0-33-8
			140	2 (P)	0-05-6
			140	1 (P)	0-00-7
			152	7B (P)	0-13-4
			152	7A (P)	0-04-5
			152	5 (P)	0-00-2
			154	9 (P)	0-11-3
			154	8 (P)	0-00-2
			154	7 (P)	0-03-7
			154	5(P)	0-13-4
			155	3 + 4A (P)	0-12-0
			157	1D(P)	0-01-0
			158	2 (P)	0-03-1
			164	4 (P)	0-03-4
			164	2 (P)	0-02-7
			58	1 (P)	0-01-5
			60	5 (P)	0-01-5
			60	6 (P)	0-02-3
			60	4B(P)	0-01-5
			67	5 (P)	0-01-0

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

का. आ. 457:—पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 2 की धारा (अ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नीचे दी गयी अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम (3) का तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित थोत की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

अधिकृत का नाम	पता	क्षेत्रीय सीमा
स्पेशल उप-जिला- अधिकारी	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कृष्णा गोवाबरी परियोजना, प्रकाश नगर, राजामुद्री, पिन-533103 (आ०.प्र.)	आन्ध्र प्रदेश

[संख्या ओ-12017/1/87-ओ.एन.जी./डी-4]

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 29th Jan., 1988.

S. O. 457.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column I of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in the column of the said schedule.

## SCHEDULE

Name of Person	Address	Teritorial Jurisdiction
Special Deputy Collector (LQ)	Oil & Natural Gas Commission, KG Project, Prakash Nagar, Rajahmundry-533 103(AP)	State of Andhra Pradesh

[No. O-12017/1/87-ONG/D.4]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1988

का. आ. 458:—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से घुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

और, यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिलाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षाते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिलाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

## अनुसूची

गांधार से घुवारण तक पाइप लाइन बिलाने के लिए  
राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—आमोद

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
1	2	3	4	5
मंछासरा	237	0	03	36
	236	0	17	50
	235	0	16	10
	234	0	48	13
	233	0	06	12
	221	0	71	80
	225	0	01	60
	224	0	26	05
	223	0	48	60
	205	0	14	40
	204	0	13	20
कार्ट ट्रैक		0	07	50
	395	0	00	24
	396	0	04	50
	397	0	14	76
	398	0	14	19
	399	0	08	10
	415	0	28	32
	414	0	08	25
	413	0	20	10
	424	0	00	37
	425	0	09	80
	426	0	15	35
कार्ट ट्रैक		0	06	60
	436	0	18	00

[प्रतीक्षा ३(ii)]

भारत का राजपत्र : मार्च 5, 1988 / काल्पन 15, 1909

1	2	3	4	5
	कार्ट्ट्रेक	0	06	30
634		0	04	75
636		0	16	85
639		0	00	05
635		0	02	38
640		0	34	50
641		0	05	10
642		0	34	95
	कार्ट्ट्रेक	0	09	00
729		0	09	60
728		0	22	50
725		0	00	36
724		0	01	47
723		0	21	25
722		0	07	69
714		0	06	75
718		0	01	04
717		0	09	30
716		0	12	30
715		0	11	76
704/ए/बी		0	48	00
705		0	03	37
706		0	29	60
709		0	00	35
708		0	01	62
707		0	05	18
726		0	09	00

[स. ओ 11027/22/88-ओ एन जी-जीIII]

New Delhi, the 1st February, 1988

S.O. 458.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline, (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE  
PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Block No.	Hec.	Arc.	Cent.
1	2	3	4	5
Manchhasara	237	0	03	36
	236	0	17	50
	235	0	16	10
	234	0	48	13
	233	0	06	12
	221	0	71	80
	225	0	01	60
	224	0	26	05
	223	0	48	60
	205	0	14	40
	204	0	13	20
Cart track	0	07	50	
	395	0	00	24
	396	0	04	50
	397	0	14	76
	398	0	14	19
	399	0	08	10
	415	0	28	32
	414	0	08	25
	413	0	20	10
	424	0	00	37
	425	0	09	80
	426	0	15	35
Cart track	0	06	60	
	436	0	18	00
Cart track	0	06	30	
	634	0	04	75
	636	0	16	85
	639	0	00	05
	635	0	02	38
	640	0	34	50
	641	0	05	10
	642	0	34	95
Cart track	0	09	00	
	729	0	09	60
	728	0	22	50
	725	0	00	36
	724	0	01	47
	723	0	21	25
	722	0	07	69
	714	0	06	75
	718	0	01	04
	717	0	09	30
	716	0	12	30
	715	0	11	76
704/A/B	0	48	00	
	705	0	03	37
	706	0	29	60
	709	0	00	35
	708	0	01	62
	707	0	05	18
	726	0	09	00

[No. O-11027/22/88-ONG/D-III]

का. ओ. 459:—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि स्थानिकता में यह आवश्यक है कि गंगरात राज्य में गंधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के पद्धिहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिभार्ता जानी जाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एक्सप्रेस अनुमति में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्तव कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि सकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के माफत।

#### अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—पादरा

गांव	ब्लौक नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पावडा	307	0	10	50
	308	0	08	10
	309	0	16	20
	310	0	08	70
	312	0	08	70
	313	0	16	20
	314	0	16	40
	315	0	11	16
	403	4	99	96

[सं. ओ-11027/23/88-ओ एन जी /डी.-III]

S.O. 459.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent

Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And, every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat	District : Vadodra	Taluka : Padra	Village	Block No.	Hec.	Arc	Cent.
1	2	3	4	5			
Pawada	307	0	10	50			
	308	0	08	10			
	309	0	16	20			
	310	0	08	70			
	312	0	08	70			
	313	0	16	20			
	314	0	16	40			
	315	0	11	16			
	403	4	99	96			

[No. O-11027/23/88-ONG/D-III]

का. आ. 460:—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एक्सप्रेस अनुमति में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्तव कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो हो या किसी विधि व्यवसायी के माफत

## अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात ज़िला—बडोदरा तालुका—पादरा

गांव	ज़िलाक नं.	लेटरेयर आरे.	सेटीयर	
1	2	3	4	5
भजातम	435	0	42	30
	437	0	17	55
	438	0	16	95
	439	0	04	62
	440	0	02	63
	434	0	14	56
	429	0	02	20
	430	0	25	50
	431	0	27	90
कार्ट ट्रैक	0	03	60	
	396	0	12	75
	395	0	10	22
	389	0	55	24
	365	0	50	10
	372	0	00	45
	366	0	29	55
	367	0	12	60
	368	0	17	02
	369	0	05	94
	355	0	06	90
कार्ट ट्रैक	0	32	81	
	119	0	14	25
	132	0	41	76
	131	0	09	30
	130	0	09	30
	129	0	06	50
	142	0	17	42
	143	0	10	12
	144	0	01	50
	145	0	07	92
	146	0	00	70

[सं. ओ—11027/24/88—ओ. एन. जी. ई. III]

S.O. 460.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Padra	Village	Block No.	Hec.	Are	Cen.	
				1	2	3	4	5
			Majatam	435	0	42	30	
				437	0	17	55	
				438	0	16	95	
				439	0	04	62	
				440	0	02	63	
				434	0	14	56	
				429	0	02	20	
				430	0	25	50	
				431	0	27	90	
			Cart track	0	03	60		
				396	0	12	75	
				395	0	10	22	
				389	0	55	24	
				365	0	50	10	
				372	0	00	45	
				367	0	29	55	
				368	0	17	02	
				369	0	05	94	
				355	0	06	90	
			Cart track	0	32	81		
				119	0	14	25	
				132	0	41	76	
				131	0	09	30	
				130	0	09	30	
				129	0	06	50	
				142	0	17	42	
				143	0	10	12	
				144	0	01	50	
				145	0	07	92	
				146	0	00	70	

[No. O—11027/24/88—ONG D. III]

का. आ. 461.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिये पानडुपाबद्ध पतुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमुद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेंल नदी प्राकृतिक गेम आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, गांधरपुरा गोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट है, कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

### अनुसूची

गांधर से ध्वारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—बडोदरा तालुका—पादग

गांव	नामक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेटीयर	1	2	3	4	5
चौकारी	381	0	21	00			125	0	13
	379	0	15	90			129	0	04
	378	0	05	50			130	0	25
	377	0	00	50			131	0	15
	375	0	14	43			57	0	00
	376	0	01	74			54/सी	0	09
	375	0	13	50			54/बी	0	00
	368	0	01	20			54/ए	0	01
	370	0	06	30			कार्ट ट्रैक	0	03
	369	0	08	40			49	0	15
	367	0	17	40			1127/ए-बी	01	67
	362	0	15	90					84
	358	0	08	20					50
	363	0	04	35					
	357	0	06	86					
	356	0	06	30					
कोर्ट ट्रैक		0	03	00					
	353	0	08	37					
	354	0	08	44					
	355	0	00	20					
	346	0	06	52					
	286	0	07	42					
	289	0	27	00					
	290	0	05	94					
	391	0	16	72					
	356	0	00	40					
	33	0	18	22					
	334	0	28	50					

S.O. 461—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

[म. ओ. 11027/25/88-ओ. एन. जी. डी. III]

## SCHEDULE I

## PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State	Gujarat	District	Vadodara	Taluka	Padra
Village		Block No.	H.	Arc	Cont
1	2	3	4	5	
Chokari		381	0	21	00
		379	0	15	90
		378	0	05	50
		377	0	00	50
		375	0	14	43
		376	0	01	74
		374	0	13	50
		368	0	01	20
		370	0	06	30
		369	0	08	40
		367	0	17	40
		362	0	15	90
		358	0	08	20
		363	0	04	35
		357	0	06	86
		356	0	06	30
	Cart track	0	03	00	
		353	0	08	37
		354	0	08	44
		355	0	00	20
		348	0	06	52
		286	0	07	42
		289	0	27	00
		290	0	05	94
		291	0	16	72
		336	0	00	40
		335	0	18	22
		334	0	28	50
		330	0	07	70
		331	0	08	80
		320	0	10	72
		319	0	02	76
		321	0	14	56
	Cart track	0	03	00	
		188	0	42	00
		189	0	00	35
		166	0	09	60
		167	0	09	30
		168	0	22	20
		169	0	21	62
		163	0	14	37
	Cart track	0	03	00	
		126	0	32	82
		128	0	00	18
		125	0	13	88
		129	0	04	50
		130	0	25	12
		131	0	15	00
		57	0	15	00
		54/C	0	09	00
		54/B	0	09	00
		54/A	0	01	35
	Cart track	0	03	00	
		49	0	15	67
		1127/A-B	0	84	50

का. अ. 462 —यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गाधार से धुवारण तक पैद्योलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा विछाई जानी चाहिए।

और यह यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुबाद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अत अब पैद्योलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वश्वर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई अविस्त, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सम्म ग्राहिकारी, नेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग निर्माण और देवद्वाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़दा-9 को इस अधिसूचिना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

## अनुसूची

गाधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला बडोदरा तालुका पादरा

	गांव	ब्लाक नं	हेक्टेयर	आरे	सेंटी
				5	यर
	1	2	3	4	5
चिंताल	.	113	0	09	90
		19	0	23	70
		356	0	20	10
		116	0	01	00
		118	0	28	72
		117	0	03	24
		120	0	32	55
		121	0	08	70
	कार्ट ट्रैक		0	05	85
		102	0	15	62
		103	0	33	90
	कार्ट ट्रैक		0	06	00
		164	0	06	75
		165	0	33	30
		166	0	22	20

1	2	3	4
विनाल-जारी	167	17	17
	171	0	05
	168	0	00
	170	0	34
	169	0	02
	180	0	14
	181	0	24
	193	0	06
	192	0	10
कार्ट ट्रैक	0	03	30
357	0	36	20
243	0	01	08
240	0	13	44
241	0	25	58
कार्ट ट्रैक	0	03	30
272	0	27	00
273	0	22	20
312	0	15	60
310	0	15	90
311	0	16	90
309	0	07	20
314	0	24	37
301	0	00	08
315	0	00	27
316	0	29	88
317	0	07	50
324	0	01	40
323	0	51	48
322	0	01	54
321	0	01	44

[सं. ओ. 11027/26/88—ओएन जी डी-III]

S.O. 462.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Padra		
		Village	Block No.	Hec. Are Cent.
		1	2	3 4 5
		Chitral	113	0 09 90
			19	0 23 70
			356	0 20 10
			116	0 01 00
			118	0 28 72
			117	0 03 24
			120	0 32 55
			121	0 08 70
		Cart track	0	05 85
			102	0 15 62
			103	0 33 90
		Cart track	0	06 00
			164	0 06 75
			165	0 33 30
			166	0 22 20
			167	0 17 28
			171	0 05 25
			168	0 00 90
			170	0 34 75
			169	0 02 45
			180	0 14 80
			181	0 24 30
			193	0 06 60
			192	0 10 64
		Cart track	0	03 30
			357	0 36 20
			243	0 01 08
			240	0 13 44
			241	0 25 58
		Cart track	0	03 30
			272	0 27 00
			273	0 22 20
			312	0 15 60
			310	0 15 90
			311	0 16 90
			309	0 07 20
			314	0 24 37
			301	0 00 08
			315	0 00 27
			316	0 29 88
			317	0 07 50
			324	0 01 40
			323	0 51 48
			322	0 01 54
			321	0 01 44

[No. O-11027/26/88-ONG D.III]

का आ. 463.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पैदेसियम के परिवहन के लिए पाहपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वापद्म अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूगि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)। अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निमणि और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन्। यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यावसायी के माफ़त।

अनसची

गांधार में धुवारण तक पाइपलाईन विस्थाने के लिए  
राज्य—गुजरात ज़िला—सौंदर्या तालुक पाटीरा

गांधी	ल्लाक न	हैंडर	आर	सेन्टी- यर
सांडा	277	0	40	5
	278	0	24	24
	279	0	00	66
कार्ट ट्रैक		0	03	90

[सं ओ. - 11027/37/88-ओ एन जी ई-III]

S.O. 463.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009):

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

**SCHEDULE E**

## **PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN**

State : Gujarat      District : Vadodara      Taluka : Padra

Village	Block No.	Hec.	Are	Cumulative
1	2	3	4	5
Sandha	277	0	40	50
	278	0	24	24
	279	0	00	66
	Cart track	0	03	90

[No. Q-11027/27/88-ONG D.III]

का. आ. 164.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात भाज्य में गांधीर से धुवारण तक पैदेनियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिल्डर्इ जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को छिनने के प्रयोजन के लिये एतदपावन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अब वैक्योनियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उप-योग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करते का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

ब्रशर्टें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देशभाल न भाग, मकरापुरा रोड़, बड़ौदा-९ को इस अधिसूचना की तारीख से २१ दिनों के भीतर कर सकेगा।

• और एंसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति धिनिदिष्टतः  
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी  
मुन्त्राई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी  
मार्फत ।

अनंत सच्ची

गांधार में धुवारण तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात		जिला—बडोदरा		तालुका—पादरा	
गाव	ब्लॉक	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर सेन्टीयर	
नं.					
1	2	3	4	5	6
मोभो	256	178	0	30	42
	260	179	0	08	10
	259	188 और 189	0	32	66

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
265	187		0	00	04		923	767	0	02	10
271	186		0	30	40		916/पं	768	0	09	45
266	185/2		0	16	34		913	769	0	15	10
270	191/1 और 194/3	0	05	98			914/श्री	822	0	00	20
269	194/2		0	01	54		912	770	0	17	04
267	195 और 196	0	19	89			669/पं	817	0	00	14
							911	1507/पं	0	05	50
283	197		0	35	25		909	776	0	22	36
कार्ट ट्रैक	—		0	07	15		670/पं	773 और 775	0	13	50
331	253/2		0	01	26				[स. अ.-11027/28/88 ओ पन जी इ-III]		
327	225 और 226	0	16	44							
328	227 और 228	0	17	35							
329	250/1		0	01	43						
325	229		0	21	05						
324	230 और 248	0	22	75							
321	232		0	07	25						
316	233		0	39	51						
315	234 और 237/2/1	70	15	10							
314	237 और 2/2	0	00	76							
312	235		0	24	36						
313	236		0	01	50						
311	219		0	02	24						
कार्ट ट्रैक	—	09	09	74							
463	402 और 403	0	17	55							
467	406		0	11	58						
466	405		0	05	77						
468	407		0	21	90						
469	409		0	16	50						
465	408		0	11	40						
461	394		0	10	50						
460	397		0	05	70						
459	306		0	23	40						
कार्ट ट्रैक	—		0	04	20						
530	464		0	22	91						
531	464/2		0	00	76						
528	465 और 465/1	0	60	00							
कार्ट ट्रैक	..		0	07	05						
920	824		0	13	50						
919	823/1		0	51	15						
918	823		0	13	71						
917	823/पं		0	05	75						
कार्ट	—		0	13	50						
ट्रैक											

S.O. 464.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State: Gujarat      District : Vadodara      Taluka , Padra

Village	Block No.	Survey No.	Hect- are	Acre	Cen- tiare
1	2	3	4	5	6
MOBHA	256	178	0	30	42
	269	179	0	08	10
	259	188 & 189	0	32	66
	265	187	0	00	04
	271	186	0	30	40
	266	185/2	0	16	34
	270	191/1 & 194/3	0	05	98
	269	194/2	0	01	54
	267	195 & 196	0	19	89
	283	197	0	35	25
	Cart tract <sup>1</sup>	—	0	07	15
	331	253/2	0	01	26
	327	225 & 226	0	16	44
	328	227 & 228	0	17	35
	329	250/1	0	01	43

1	2	3	4	5	6
	325	229	0	21	05
	324	230 & 248	0	22	75
	321	232	0	07	25
	316	233	0	39	51
	315	234 & 237	0	15	10
		237/2/1			
	314	237/2/2	0	00	76
	312	235	0	24	36
	313	236	0	01	50
	311	219	0	02	24
	Cart track	—	0	09	74
	463	402 & 403	0	17	55
	467	406	0	11	58
	466	105	0	05	77
	468	407	0	21	90
	469	409	0	16	50
	465	408	0	11	40
	461	394	0	10	50
	460	397	0	05	70
	459	306	0	23	40
	Cart track	—	0	04	20
	530	464	0	22	91
	531	464/2	0	00	76
	528	465 & 465/1	0	60	00
	Cart track	—	0	07	05
	920	824	0	13	50
	919	823/1	0	51	15
	918	823	0	13	71
	917	823/P	0	05	75
	Cart track	—	0	13	50
	923	767	0	02	10
	916/A	768	0	09	45
	913	769	0	15	10
	914/B	822	0	00	20
	912	770	0	17	04
	669A	817	0	00	14
	911	1507/P	0	05	50
	909	776	0	22	36
	970/A	773 & 775	0	13	50

[No. O-11027/28/88-ONG D III]

का आ. 465.—यत्. केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत् यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एक्सप्रोबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यत् श्रव पेट्रोलियम और स्वनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्कियां का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और

देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवाधी के मार्फत।

### अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाईग लाइन बिछाने के लिए।

गज्य—गुजरात जिला—वडांशग तालुका—पादरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	मेन्टीयर
1	2	3	4	5
पीडिपा	370	0	00	42
	371	0	36	75
	—	0	07	13
	378	0	04	59
	376	0	07	40
	377	0	20	91
	374	0	06	30
कार्ट ट्रैक	0	03	00	
	386	0	24	25
	385	0	04	90
	383	0	33	90
	411	0	33	00
	410	0	12	00
कार्ट ट्रैक	0	02	55	
	422	0	49	55
	425	0	19	20
	424	0	00	40
	475	0	17	56
	493	0	04	76
	476	0	10	12
	477	0	03	45
	488	0	41	22
	480	0	00	81
	481	0	28	92
कार्ट ट्रैक	0	04	80	
	559	0	19	20
	561	0	17	00
	558	0	29	05
	557	0	04	56
	564	0	39	60
	566	0	16	50
	574	0	21	60
	573	0	32	20
	580	0	00	52

1	2	3	4	5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
581	0	12	66		481	0	28	92	
582	0	33	45		Cart track	0	04	80	
580	0	04	25		559	0	19	20	
579	0	17	55		561	0	17	00	
583	0	00	40		558	0	29	05	
					557	0	04	56	
					564	0	39	60	
					566	0	16	50	
					574	0	21	60	
					573	0	32	20	
					580	0	00	52	
					581	0	12	66	
					582	0	33	45	
					580	0	04	25	
					579	J	17	55	
					583	0	00	40	

[सं. ओ.-11027/29/88-ओ.एन.जो.डॉ. III]

S.O. 465.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereunto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (J) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user thereon:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### CHEQUE

#### Pipeline from GANDHAR TO DHUVARAN.

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padara

Village	Block No.	Hect- are	Cen- ti- are	
1	2	3	4	5
PINDPA	370	0	00	42
	371	0	36	75
	—	0	07	13
	378	0	04	59
	376	0	07	40
	377	0	20	91
	374	0	06	30
	Cart track	0	03	00
	386	0	24	25
	385	0	04	90
	383	0	33	90
	411	0	33	00
	410	0	12	00
	Cart track	0	02	55
	422	0	49	55
	425	0	19	20
	424	0	00	40
	475	0	17	56
	493	0	04	76
	476	0	10	12
	477	0	03	45
	488	0	41	22
	480	0	00	81

[No. O—11027/29/88—ONG D.III]

का. आ. 466—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार में धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और ग्वनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियमित और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी मुनाफाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

#### अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य:—गुजरात जिला:—बड़ौदा तालुका:—पादरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	भर	सेन्टोयर
1	2	3	4	5
कणमठ	613	0	04	50
	604	0	11	86
	605	0	08	26

1	2	3	4	5
कण्ठट-समाप्त	606	0	23	70
	602	0	12	60
	608	0	42	00
	609	0	01	96
काटे ट्रैक		0	01	81
	594	0	06	90
	593	0	11	70
	091	0	35	52
	580	0	23	25
581/A-बी		0	39	30
	569	0	00	49
	568	0	12	34
	567	0	05	10
	562	0	00	14
काटे ट्रैक		0	06	00
407/ए-बी		0	13	95
	409	0	29	19
	521	0	02	92
	387	0	32	08
	385	0	00	28
	377	0	14	04
	381	0	18	36
	379	0	13	69
	380	0	11	05
	326	0	28	22
	341	0	13	75
	327	0	15	15
	328	0	15	30
330/A-बी		0	24	00
	303	0	15	60
	302	0	05	60
	301	0	11	80
	232	0	12	00
	231	0	07	87
	234	0	01	05
	229	0	38	93
	228	0	20	16
	227	0	05	46
	1167	0	00	28
	210	0	29	10
	225	0	05	72
	221	0	18	30
	220	0	00	64
	222	0	15	96
	219	0	16	75
	340	0	07	02

S.O. 466.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat      District : Vadodara      Taluka : Padara

Village                  Block No.      Hectare      acre      Cen-

ti-  
are

KANZAT	1	2	3	4	5
	613	0	04	50	
	604	0	11	86	
	605	0	08	26	
	606	0	23	70	
	602	0	12	60	
	608	0	42	00	
	609	0	01	96	
Cart track	0	01	81		
	594	0	06	90	
	593	0	11	70	
	591	0	35	52	
	580	0	23	25	
581/A-B	0	39	30		
	569	0	00	49	
	568	0	12	34	
	567	0	05	10	
	562	0	00	14	
Cart track	0	06	00		
407/A-B	0	13	95		
	409	0	29	19	
	521	0	02	92	
	387	0	32	08	
	385	0	00	28	
	377	0	14	04	
	381	0	18	36	
	379	0	13	69	
	380	0	11	05	
	326	0	28	22	
	341	0	13	75	
	327	0	15	15	
	328	0	15	30	
330/A-B	0	24	00		
	303	0	15	60	
	302	0	05	60	
	301	0	11	80	

1	2	3	4	5	6
Kanzat-concl.		232	0	12	00
		231	0	07	87
		234	0	01	05
		229	0	38	93
		228	0	20	16
		227	0	05	46
		1167	0	00	28
		210	0	29	10
		223	0	05	72
		221	0	18	30
		220	0	00	64
		222	0	15	96
		219	0	16	75
		340	0	07	02

[No. O-11027/30/88-ONG. D.III]

क. आ। सं. 467 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिल्डर्ड जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बास्तें कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदिगा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वयं से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

#### अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाइप लाइन विछाने के लिए।

राज्य:—गुजरात जिला—भरुच तालुका—आयोग

गाव	व्याक नं.	हैक्टेयर	धारा	मैट्रीयर
देणवा	755	0	00	90
	756	0	12	32
	757	0	29	41
	758	0	16	80
	759	0	14	10

[स. अं—11027/31/88—ओ एन जी डी-III]

S.O. 467.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009):

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

#### SCHEDULE

##### Pipeline From Gandhar To Dhuvaran

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Block No.	Hect-are	Arc-	Centi-	tarci
	1	2	3	4	5
DENVA		755	0	00	90
		756	0	12	32
		757	0	29	41
		758	0	16	80
		759	0	14	10

[No. O-11027/31/88-ONG-D.III]

का. आ. म. 468 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिल्डर्ड जानी चाहिए।

आंग यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसी उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बास्तें कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदिगा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ओर ऐसा आधेष्ट करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह आहता है कि उसकी मुनवाई अवित्तन स्थ में हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़ित !

## अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाईप लाइन विलानि के लिए ।

राज्य:—गुजरात जिला भरुच तालका—आमोद

गांव	ब्लॉक न.	हेक्टेयर	आर	मेट्रीयर
1	2	3	4	5
मांगरोल	644	0	28	50
	642	0	04	00
	646	0	19	44
	647	0	09	60
	661	0	21	00
	662	0	18	90
	634	0	28	50
	635	0	00	13
	632	0	06	60
	629	0	07	56
	630	0	32	94
	627	0	15	30
	620	0	21	00
	618	0	24	00
	617	0	11	40
	613	0	28	20
	612	0	09	45
काट ट्रैक	0	19	50	
583	0	32	40	
584	0	05	40	
589	0	20	52	
592	0	33	72	
काट ट्रैक	0	09	00	
473	0	30	60	
474	0	30	45	
488	0	23	37	
472	0	30	00	
489	0	06	36	
464	0	03	12	
461	0	10	99	
460	0	07	20	
452	0	09	00	
451	0	02	80	
453	0	45	20	

[सं ओ 11027/32/88—ओ०ए०जी०डी-III]

S.O. 468—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of Use in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of use therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Block No.	Hect- are	Acre Cen- tre	1	2	3	4	5
MANGROL	644	0	28	50				
	642	0	04	00				
	646	0	19	44				

	1	2	3	4	5
MANGROL—Contd					
647		0	02	60	
661		0	21	00	
662		0	18	90	
634		0	24	50	
635		0	01	13	
672		0	06	00	
629		0	07	56	
630		0	32	94	
627		0	15	30	
620		0	21	00	
614		0	24	00	
617		0	11	40	
613		0	28	20	
612		0	09	45	
Cat track		0	19	50	
553		0	32	40	
554		0	05	40	
559		0	20	52	
522		0	33	72	
Cat track		0	09	00	
573		0	30	60	
574		0	30	45	
578		0	23	37	
572		0	30	00	
459		0	06	36	
441		0	03	12	
461		0	10	99	
430		0	07	20	
42		0	09	00	
451		0	02	80	
473		0	45	20	
Cat track		0	04	50	
404		0	19	20	
411		0	19	05	
403		0	00	15	
356		0	91	09	
400		0	03	80	
359		0	02	21	
378		0	01	90	
397		0	11	13	
Cat track		0	04	50	
371		0	21	45	
330		0	23	25	
139		0	31	20	
338		0	11	37	
371		0	34	65	
341		0	11	20	
321		0	13	20	
319		0	21	00	
342		0	01	05	
318		0	23	25	
317		0	00	75	

[No. O—11027/3<sup>o</sup> 8<sup>o</sup>/ONG D III]

का. आ. 469—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गंजरात राज्य में गधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत् यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एटदपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अत् अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एटदपावद घोषित किया है।

वर्षामें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्तम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण आर डेवलपमेंट प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

आर एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विशेष व्यवसायी के माफेत।

### अनुसूची

गधार में धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गंजरात जिला—सूचना तालुका—जबुसर

गाव	लोकान	हेक्टेयर			आर	गंन्टीयर
		1	2	3	4	5
उच्छुद	507		0	02	10	
	508		0	30	10	
	509		0	13	56	
	510		0	00	78	
	—		0	05	35	
	188		0	00	98	
	487		0	19	83	
	511		0	07	12	
	485		0	01	00	
	486/ए-बी		0	16	65	
	484		0	04	62	
	483		0	11	70	
	475		0	46	50	
	476		0	09	90	
	454		0	21	22	
फार्ट ट्रैक			0	03	30	
	515		0	44	70	
	532		0	22	84	
	525		0	06	21	
	526		0	02	40	
	528		0	11	70	
	530		0	70	00	
	529		0	05	80	
	535		0	21	90	
	547		0	00	16	
	546		0	17	24	

1	3	3	4	5	1	2	3	4	5
545	0	09	40		511	0	07	12	
538	0	04	40		485	0	01	00	
543	0	00	60		486/A-B	0	16	63	
541	0	05	79		484	0	04	62	
542	0	07	20		483	0	11	70	
565	0	02	25		475	0	46	50	
566	0	11	55		476	0	09	90	
564	0	09	60		454	0	21	22	
567	0	01	92		Cart track	0	03	30	
568	0	05	28		515	0	44	70	
569	0	09	39		532	0	22	84	
574	0	00	12		525	0	06	21	
570	0	20	81		526	0	02	40	
571	0	14	52		528	0	11	70	
572	0	00	90		530	0	70	00	
काटे ट्रैक	0	09	15		529	0	05	80	
576	0	17	15		535	0	21	90	
					547	0	00	16	
					546	0	17	24	
					543	0	09	40	
					538	0	04	40	
					543	0	00	60	
					541	0	05	79	
					542	0	17	20	
					565	0	02	25	
					566	0	11	55	
					564	0	09	60	
					567	0	01	92	
					568	0	05	28	
					569	0	09	39	
					574	0	00	12	
					570	0	20	81	
					571	0	14	52	
					572	0	00	90	
					Cart track	0	09	15	
					576	0	17	15	

[मं. ओ.—11027/33/88—ओ एन झी-III]

S.O. 469.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### Pipeline From Gandhar To Dhuvaran

State : Gujarat      District : Bharuch      Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect-	Are	Con-	tiare
1	2	3	4	5	
UCHHAD	507	0	02	40	
	508	0	30	10	
	509	0	13	56	
	510	0	00	78	
	—	0	05	35	
	488	0	00	98	
	487	0	19	83	

[No. O—11027/33/88—ONG.D.III]

का. ओ. 470.—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभादि जाती चाहिए।

और यत्: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एन्डोप्रद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्डोप्रद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः  
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई  
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

## अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—बागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर	मेन्टीयर
चांचवेल	284	02	49	48
	282	02	42	35
	288	04	46	68
	290	0	47	52
	291	0	30	79
	294	0	28	80
	300	0	47	44
	296	0	03	64
	299	0	02	20
	297	0	34	90
	298	0	36	00
	315	0	66	00
	316	0	30	60
	317	0	14	10
	318	0	16	50
	319	0	36	00
	324	0	62	40
	327	0	09	00
	328	0	16	50
	330	0	42	60
	331	0	36	30

[सं. ओ.—11027/34/88—ओ एन जी डी-III]

S.O. 470.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvoran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN  
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Waoara

Village	Block No.	Hect- are	mre	Cen- tiare
Chanchvel	284	02	49	48
	282	02	42	35
	288	04	46	68
	290	0	47	52
	291	0	30	79
	294	0	28	80
	300	0	47	44
	296	0	03	64
	299	0	02	20
	297	0	34	90
	298	0	36	00
	315	0	66	00
	316	0	30	60
	317	0	14	10
	318	0	16	50
	319	0	36	00
	324	0	62	40
	327	0	09	00
	328	0	16	50
	330	0	42	60
	331	0	36	30

[No. O—11027/34/88—ONG. D.III]

का. ओ. 471—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्धारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निमिण और देखभाल प्रभाग, मकर रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

## अनुसूचि

गांधार से धुकारण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात	जिला-भरुच	तालुका	आमोद	
गाँव	बलोक नं	हेक्टर	आर से.	
1	2	3	4	5
बालीपुर	कार्ड्र ट्रक	0	03	60
	455	0	12	00
	453	0	34	21
	454	0	04	50
	452	0	74	40
	451	0	60	45
	450	0	06	71
	107	0	21	30
	109	0	21	30
	110	0	04	80
	111	0	04	80
	112	0	03	30
	113	0	06	00
	115	0	23	00
	116	0	03	40
	120	0	13	20
	119	0	14	10
	165	0	46	32
	166	0	17	00
	164	0	13	60
	163	0	33	08
	171	0	07	37
	173	0	02	67
	170	0	49	15

[सं. ओ-11027/35/88-ओएनजीई-III]

S.O. 471.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Block No.	Hect-are	Cen-taro
VALIPUR	Caritrack	0 03	60
	455	0 12	00
	453	0 34	21
	454	0 04	50
	452	0 74	40
	451	0 60	45
	450	0 06	71
	107	0 21	30
	109	0 04	80
	110	0 04	80
	111	0 03	30
	112	0 03	30
	113	0 06	00
	115	0 23	00
	116	0 03	40
	120	0 13	20
	119	0 14	10
	165	0 46	32
	166	0 17	00
	164	0 13	60
	163	0 33	08
	171	0 07	37
	173	0 02	67
	170	0 49	15

[No. O-11027/35/88-ONG-D III]

का. आ. 472:—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुकारण तक, पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहाहा।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावल अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की शारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा धोषित किया है।

वशते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अनुसूचिना को तारोद्व से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट है कि वह भी कथन करेगा कि क्या यह आहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची		1	2	3	4	5
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	सें.		
1	2	3	4	5		
अभोल	285	0	25	34		
	287	0	05	98	723	0 00 57
	284	0	01	75	727	0 35 54
	288	0	22	70	728	0 00 24
	316	0	00	56	730	0 31 05
	315	0	32	43		
	314	0	55	04		
	313	0	03	00		
कार्ट्रेक		0	02	55		
	312	0	19	05		
	335	0	48	90		
	336	0	15	60		
	337	0	10	08		
	338	0	00	25		
	340	0	18	05		
	339	0	27	00		
कार्ट्रेक		0	03	60		
	249	0	46	65		
	342	0	21	75		
कार्ट्रेक		0	03	90		
	42	0	20	40		
	41	0	15	75		
	43	0	16	50		
	45	0	33	30		
	44	0	06	27		
	52	0	56	04		
	54	0	01	65		
कार्ट्रेक		0	03	00		
	30	0	38	55		
	61	0	44	88		
	27	0	03	50		
	63	0	03	42		
	62	0	31	05		
कार्ट्रेक		0	13	60		
	754	0	09	78		
	753	0	54	75		
कार्ट्रेक		0	02	70		
	751	0	24	60		
	740	0	39	60		
	973	0	24	35		

[सं. ओ. 11027/36/88-ओ एन जी झी III]

S.O. 472.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

#### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat      District : Vadodara      Taluka : Padara

Village	Block No.	Hect-are	Arc-	Centi-
1	2	3	4	5
ABHOL	285	0	25	34
	287	0	05	98
	284	0	01	75
	288	0	22	70
	316	0	00	56
	315	0	32	43
	314	0	55	04
	313	0	03	00
	Cart track	0	02	55
	312	0	19	05
	335	0	48	90
	336	0	15	60
	337	0	10	08
	338	0	00	25
	340	0	18	05
	339	0	27	00
	Cart track	0	03	60
	249	0	46	65
	342	0	21	75
	Cart track	0	03	90
	42	0	20	40
	41	0	15	75
	43	0	16	50
	45	0	33	30
	44	0	06	27
	52	0	56	04
	54	0	01	65
कार्ट्रेक				
	30	0	38	55
	61	0	44	88
	27	0	03	50
	63	0	03	42
	62	0	31	05
कार्ट्रेक				
	754	0	09	78
	753	0	54	75
कार्ट्रेक				
	751	0	24	60
	740	0	39	60
	973	0	24	35
	52	0	56	04

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	54	0	01	56					
	Cart track	0	03	00					
	30	:	38	55		40/3	0	00	48
	61	0	34	88		40/5	0	02	85
	27	0	03	50		41/15	0	07	16
	63	0	03	42		41/16	0	04	32
	52	0	31	05		41/14	0	31	25
	Cart track	0	13	60		47/1	0	00	20
	754	0	09	78		46/4	0	13	60
	653	0	54	75		46/3	0	12	45
	Cart track	0	02	70		46/2	0	05	10
	751	0	24	60		46/1	0	07	80
	740	0	39	60		41/11	0	07	25
	739	0	24	35		41/10	0	02	97
	723	0	00	57		41/9	0	02	52
	727	0	35	54					
	728	0	00	24					
	730	0	31	05					

[No. O-11027/36/88-ONG D.JII]

का. आ. 473—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकसभित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गाधार में धुशारण तक, पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्यपावद्ध श्रनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पार्क्सलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एत-द्वारा धोखित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबड़ु कोई व्यक्ति उम्मीदवार के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस शायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुग, रोड, बडौदरा-9 को इम प्राधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर देगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः  
यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी  
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी  
की भाफ्त।

अनुसूची

गाधार से धुवारण नक पाईप लाईन बिछाने के लिए  
राज्य-गुजरात जिला-भरुच तालुका-आमोद

ग्राव	सर्वे नं.	हे.	आर.	से.
1	2	3	4	5
आच्छोद	40/1	0	08	60
	40/2	0	27	02

1	2	3	4	5
	40/3	0	00	48
	40/5	0	02	85
	41/15	0	07	16
	41/16	0	04	32
	41/14	0	31	25
	47/1	0	00	20
	46/4	0	13	60
	46/3	0	12	45
	46/2	0	05	10
	46/1	0	07	80
	41/11	0	07	25
	41/10	0	02	97
	41/9	0	02	52
	41/8	0	03	00
	41/7	0	00	11
	42/3	0	00	56
	42/2	0	01	02
	2/1	0	21	67
	43	0	32	15
	31/12	0	00	40
	31/11	0	01	91
	31/10/3	0	00	18
	30/10/2	0	00	18
	31/10/1	0	02	55
	32	0	24	04
	31/9	0	01	25
	31/1	0	15	30
	31/2/३	0	07	20
	31/2/८	0	06	60
	31/3	0	12	00
	31/4/1	0	04	50
	831/6	0	00	12
	831/7	0	01	48
	831/8	0	03	24
	831/9	0	05	69
	831/10	0	03	90
	831/11	0	04	20
	831/12	0	04	50
	831/13	0	04	50
	831/14	0	06	00
	831/15	0	06	00
	831/16	0	06	00
	831/17	0	04	40
	831/18	0	04	06
	831/19	0	01	61
	831/20	0	00	04

1	2	3	4	5
	26	0	34	80
	8/1	0	19	20
	8/2	0	24	00
	8/3	0	23	40
	8/4	0	31	20
9	0	01	40	
7	0	04	80	
6	0	58	68	
5/3	0	11	80	
5/2/1	0	13	21	
5/1	0	15	24	
5/2/2	0	01	36	
4/1	0	24	00	
3/2-ঠি	0	00	35	
3/2-ঠী	0	93	52	
1/ঠ	2	84	40.	
549	0	85	80	
529/6	0	24	30	
529/5	0	83	20	
529/4	0	56	30	
529/9	0	00	16	
529/3	0	58	64	
529/2/ঠি	0	436	90	
529/2/ঠি	0	36	90	
529/1/ঠি	0	19	35	
529/1/ঠি	0	19	35	
527/4	0	34	95	
527/15/1	0	30	00	
527/15/2	0	29	00	
527/15/3	0	12	96	
33	0	00	77	
24	0	03	25	

[স. ও. -11027/37/88-আন্তর্জাতিক III]

S.O. 473.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

#### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Survey No.	Hect-			Are Centi-
		are	4	5	
ACHHOD	401/	0	08	60	
	40/2	0	27	02	
	40/3	0	00	48	
	40/5	0	02	85	
	41/15	0	07	16	
	41/16	0	04	32	
	41/14	0	31	25	
	47/1	0	00	20	
	46/4	0	13	60	
	46/3	0	12	45	
	46/2	0	05	10	
	46/1	0	07	80	
	41/11	0	07	25	
	41/10	0	02	97	
	41/9	0	02	52	
	41/8	0	03	00	
	41/7	0	00	12	
	42/3	0	00	56	
	42/2	0	01	02	
	42/1	0	21	67	
	43	0	32	15	
	31/12	0	00	40	
	31/11	0	01	91	
	31/10/3	0	00	18	
	31/10/2	0	00	18	
	31/10/1	0	02	55	
	32	0	24	04	
	31/9	0	01	25	
	31/1	0	15	30	
	31/2/B	0	07	20	
	31/2/A	0	06	60	
	31/3	0	12	00	
	31/4/1	0	04	50	
	831/6	0	00	12	
	831/7	0	01	48	
	831/8	0	03	24	
	831/9	0	05	69	
	831/10	0	03	90	
	831/11	0	04	20	
	831/12	0	04	50	
	831/13	0	04	50	
	831/14	0	06	00	
	831/15	0	06	00	
	831/16	0	06	00	
	831/17	0	04	40	
	831/18	0	04	06	
	831/19	0	01	61	
	831/20	0	00	04	
	26	0	34	80	
	8/1	0	19	20	
	8/2	0	24	00	
	8/3	0	23	40	
	8/4	0	31	20	
	9	0	01	40	

1	2	3	4	5	ग्रन्तसूची
					गांधार में धुकारण तक पाइप लाईन विघ्नने के लिए
	7	0	04	80	
	6	0	58	68	
	5/3	0	11	80	राज्य—गुजरात, चिक्का—भरुच तालुका—आमोद
	5/2/1	0	13	21	
	5/1	0	15	24	
	5/2/2	0	01	36	
	4/1	0	24	00	
	3/2-D	0	00	05	
	3/2-B	0	93	52	
	1/A	2	84	40	
	549	0	85	80	
	529/6	0	24	30	
	529/5	0	83	20	
	529/4	0	56	30	
	529/9	0	00	16	
	529/3	0	58	64	
	529/2/P	0	36	90	
	529/2/P	0	36	90	
	529/1/P	0	19	35	
	529/1/P	0	19	35	
	527/4	0	34	95	
	527/15/1	0	30	00	
	527/15/2	0	29	00	
	527/15/3	0	12	96	
	33	0	00	77	
	24	0	03	25	
					गांधार
					मवेन०
					हे०
					आर०
					से०
		1	2	3	4
					5
		आमोद	553	0	29
			552	0	47
			572	0	83
			570	0	30
			563	0	61
			562	0	10
			583	0	74
			615	0	05
			614	0	86
			616	0	05
			617	0	06
			618	0	04
					35

[No. O-11027/37/88-ON. G D.III]

का. आ. 474.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह प्रावधान्यक है कि गुजरात राज्य में गांधीर से ध्वनारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विचाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

ब्राह्मणों कि उक्त भूमि मे हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईश साइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेज तथा प्राकृतिक गैंस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-९ को इस अधिसूचना की तरीक्ष से २१ दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह आहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो यह किसी विधि व्यवसायी के माफत ।

[सं. ओ. 11027/38/88—ओ एन० जी डी० III]

S.O. 474.—Whereas it appears, to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of Use in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Use in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State Gujarat : District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Amod	553	29	79	
	552	0	47	10
	572	0	83	85
	570	0	75	30
	563	0	61	50
	562	0	10	20
	583	0	74	70
	615	0	05	60
	614	0	86	64
	616	0	05	46
	617	01	06	65
	618	0	04	35
	619	0	69	90
	838	0	10	50
	837	0	30	37
	827	0	05	60
	828/4	0	00	16
	835	0	04	64
	834/2	0	52	31
	833	0	00	09
	832	0	05	20
	834/1	0	13	50
	831	0	31	50
	Cart track	0	07	50
	740/2	0	58	14
	740/1	0	15	35
	741	0	10	50
	739	0	20	60
	743	0	05	80
	738	0	00	30
	745/3	0	32	25
	745/2	0	24	14
	745/1	0	04	68
	Cart track	0	14	40
	661	0	16	80
	662	0	34	05
	760	0	00	60
	761	0	35	10
	762	0	73	65

[No. O-11027/38/88-ONG D.III]

का.आ. 475.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक, पेट्रोलियम के परिवहन लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों की बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आवश्यकतावाला घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देवभासाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर भकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्वयं में हो या किसी विधि व्यवसायी के माफत।

#### अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भस्त्र तालुका—जबुसर

गाव	ठालोक नं	हेक्टर	आर	मेन्टीयर
1	2	3	4	5
मगनाद	477	0	33	11
	482	0	01	14
	478	0	00	77
	473	0	00	98
	475	0	34	97
	476	0	02	02
	486	0	29	40
	445	0	15	45
	446	0	11	20
	448	0	05	00
	444	0	18	97
	443	0	29	99
	439	0	07	24
	441	0	13	20

1	2	3	4	5
440		0	06	75
कार्ट ट्रैक		0	04	80
393		0	05	16
392		0	01	10
398		0	21	00
396		0	35	85
399		0	00	04
410		0	19	76
409		0	00	30
कार्ट ट्रैक		0	09	60
806		0	07	20
805		0	22	65
801		0	14	90
802/ए-बी		0	11	85
786		0	28	80
780		0	01	40
779		0	33	87
777		0	01	40
778		0	03	84
734		0	00	88
735		0	39	32
736		0	00	50
720/ए		0	29	50
720/बी		0	20	10
कार्ट ट्रैक		0	06	30
837		0	23	55
838		0	02	66
886		0	00	04
885		0	30	90
884		0	21	60
881		0	02	47
882		0	10	32
883		0	49	50
947		0	40	80
875		0	06	84
948		0	51	00
949		0	15	04
951		0	32	88
954		0	02	62
952		0	41	25

[सं. ओ-11027/39/88-औन्जी-बी-III]

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat      District : Bharuch      Taluka Jamburhar

Village	Block No	Hectare	Acre	Centiare
		1	2	3
Magnad	477	0	33	11
	482	0	01	14
	478	0	00	77
	473	0	00	98
	475	0	34	97
	476	0	02	02
	486	0	29	40
	445	0	15	45
	446	0	11	20
	448	J	05	00
	444	0	18	97
	443	0	29	99
	439	J	07	24
	441	0	13	20
	440	0	06	75
Cart track	0	04	80	
	393	0	05	16
	392	0	01	10
	398	0	21	00
	396	0	35	85
	399	0	00	04
	410	0	19	76
	409	0	00	30
Cart track	0	09	60	
	806	0	07	20
	805	0	22	65
	801	0	14	90
	802/A-B	0	11	85
	786	0	28	80
	780	0	01	40
	779	0	33	87
	777	0	01	40
	778	0	03	84
	734	J	00	88
	735	0	39	32
	736	0	00	50
	720/A	0	29	50
	720/B	0	20	10
	Cart track	0	06	30
	837	0	23	55
	838	0	02	66
	886	0	00	04
	885	0	30	90

S.O. 475.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

1	2	3	4	5
	884	0	21	60
	881	0	02	47
	882	0	10	32
	883	0	49	50
	947	0	40	80
	875	0	06	84
	948	0	51	00
	949	0	15	04
	951	0	32	88
	954	0	02	62
	952	0	41	25

[No. O-11027/39/88-ONG D.III]

का.आ. 476 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से ध्वारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्डपाथड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मस्तिष्यों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्डपाथड घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राप्तिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियमण और देवभाल प्रभाग, भक्षरपुरा रोड, बख्दा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस् यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी के माफंत।

#### अनुसूची

गांधार से ध्वारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात ज़िला—भरुच तालुका—जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर	मेन्टीयर
1	2	3	4	5
अणस्वी	710	0	05	60
	711	0	33	30
	736	0	10	80
	735	0	26	74

734	0	20	52
733	0	00	25
714	0	03	51
727	0	62	90
724	0	27	10
765	0	11	12
723	0	00	44
769	0	55	88
768	0	08	99
722	0	00	02
774	0	17	61
775	0	22	50
776	0	31	15
777	0	03	20
कार्ट ट्रैक	0	06	00
626	0	05	87
625	0	31	50
624	0	00	02
612	0	35	70
575	0	08	05
576	0	18	35
577	0	17	93
621	0	00	02
578	0	04	80
580	0	00	25
609	0	25	80
608	0	09	52
594	0	40	84
607	0	01	76
595	0	03	24
596	0	14	51
598	0	13	32
597	0	22	50
534	0	09	30
533	0	25	06
536	0	25	80
537	0	10	50
538	0	07	84
530	0	02	56
542	0	24	90
435	0	00	10
436	0	23	40
437	0	38	25
432	0	01	65
431	0	20	94
439	0	03	51

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
429		0	50	29	714		0	03	51
428		0	36	95	727		0	62	90
427		0	08	58	724		0	27	10
395		0	30	58	765		0	11	12
396		0	27	00	723		0	00	44
387		0	27	60	769		0	55	88
384		0	11	95	768		0	08	99
386		0	33	15	722		0	00	02
382		0	27	00	774		0	17	61
343		0	05	40	775		0	22	50
344		0	28	26	776		0	31	15
376		0	56	55	777		0	03	20
346		0	00	44	Cart track		0	06	00
375		0	02	40	626		0	05	87
340		0	26	26	625		0	31	50
349		0	16	50	624		0	00	02
350		0	32	75	612		0	35	70
351		0	07	00	575		0	08	05
					576		0	18	35
					577		0	17	93
					621		0	00	02
					578		0	04	80
					580		0	00	25
					609		0	25	80
					608		0	09	52
					594		0	40	84
					607		0	01	76
					595		0	03	24
					596		0	14	51
					598		0	13	32
					597		0	22	50
					534		0	09	30
					533		0	25	06
					536		0	25	80
					537		0	10	50
					538		0	07	84
					530		0	02	56
					542		0	24	90
					435		0	00	10
					436		0	23	40
					437		0	38	25
					432	J	01	65	
					431		0	20	94
					439		0	03	51
					429		0	50	29
					428		0	36	95
					427		0	08	58
					395		0	30	58
					396		0	27	00
					387		0	27	60
					384		0	11	95
					386		0	33	15
					382		0	27	00
					343		0	05	40
					344		0	28	26
					376		0	56	55
					346		0	0	44
					375		0	02	40
					340		0	26	26
					349		0	16	50
					350		0	32	75
					351		0	07	00I

[सं. ओ-11027/40/88-ओएनजी-डी-III]

S.O. 476—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
ANKHI	710	0	05	60
	711	0	33	30
	736	0	10	80
	735	0	26	74
	734	0	20	52
	733	0	00	25

का. आ. 477.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजारा से उत्तराण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निमणि और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

#### अनुसूची

हजारा से उत्तराण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
वरीयाव	1164	0	43	95

[सं. ओ-11027/41/88-ओएनजी डी-III]

S.O. 477.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira to Utran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### PIPELINE FROM HAJIRA TO UTRAN

State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyasi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Variav	1164	0	43	95

[No. O-11027/41/88-ONGD.III]

का. आ. 478.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से झुआरण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निमणि और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा अक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

#### अनुसूची

गांधार से झुआरण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-बडोदरा तालुका-पाकरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कुराल	601	0	25	20
	600	0	09	75
	599	0	09	42
	588	0	53	12
	598	0	05	36
	597	0	21	22

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1988

S.O. 479.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 1199, dated the 24th April, 1987, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section (ii), dated the 9th May, 1987, in line 47, at page 1733 for “76(part) 92(part)”, read “76 to 90, 91 (part), 92 (part)”.

[No. 43015/31/85-CA/LSW]

B. B. RAO, Under Secy.

1	2	3	4	5
	587	0	09	75
	कार्ट ट्रैक	0	04	80
	554	0	31	68
	552	0	16	40
	553	0	03	41
	547	0	10	68
	546	0	10	80
	545	0	34	78
	544	0	07	92
	534	0	18	75

[स. ओ-11027/42/88-ओएनजी डी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 478.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the and described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land, may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Mukarpura Road, Vadodara, 390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## PIPELINE FROM GANDHAR TO DHUVARAN

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiar
Kural	601	0	25	20
	600	0	09	75
	599	0	09	42
	588	0	53	12
	598	0	05	36
	597	0	21	22
	587	0	09	75
Cart track	0	04	80	
	554	0	31	68
	552	0	16	40
	553	0	03	41
	547	0	10	68
	546	0	10	80
	545	0	34	78
	544	0	07	92
	534	0	18	75

[No. O-11027/42/88-ONG D. III]  
K. VIVEKANAND, Desk Officer

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1988

S.O. 479.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 1199, dated the 24th April, 1987, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section (ii), dated the 9th May, 1987, in line 47, at page 1733 for “76(part) 92(part)”, read “76 to 90, 91 (part), 92 (part)”.

[No. 43015/31/85-CA/LSW]

B. B. RAO, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1987

का.आ. 480.—भारतीय उपचर्या परिषद्, भारतीय उपचर्या परिषद्, अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की जिसे इसके पांचवां उक्त अधिनियम कहा गया है धारा 10 के अनुसरण में 5 अप्रैल, 1980 को हुई अपनी बैठक में पारित स्तम्भ द्वारा, यह घोषित किया है कि कालेज और नर्सिंग नियंत्रित अंगठी की नीचे स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त अर्द्धार्थी का नाम शैक्षणिक सत्र, 1980 से उसके स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट नाम में बदल दिया जाए।—

(1)

(2)

- 7. उपचर्या प्रशासन में डिप्लोमा) नर्सिंग शिक्षा और
- 8. नर्सिंग ट्रूट्यूट्स डिप्लोमा } प्रशासन में डिप्लोमा
- 9. मिडवाइफ ट्रूट्यूट्स डिप्लोमा ]

अत., अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,—

उक्त अनुसूची के भाग 2 में सारणी की क्रम संख्या 2 के सामने,—(1) स्तम्भ 2 में, मद 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“(जब 1980 को या उससे पहले की गई)”;

(2) स्तम्भ 2 में, मद 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“10. उपचर्या और प्रशासन में डिप्लोमा।”

[संख्या 14015/(1) 181—प्र००४८००४८०]

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 7th December, 1987

S.O. 480. Whereas, the Indian Nursing Council has, in pursuance of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), (hereinafter referred to as the said Act),

by a resolution passed at its meeting held on the 5th April, 1980, declared that the nomenclature of recognised qualifications of the College of Nursing, New Delhi, specified in column (1) below be changed with effect from academic session 1980, to those specified in column (2) thereof :—

(1)	(2)
7. Diploma in Nursing Administration,	Diploma in Nursing Education
8. Nursing Tutors Diploma	
9. Midwife Tutors Diploma	and Administration

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments to the Schedule to the said Act, namely :—

In Part II of the said Schedule, against serial number 2 of the Table.—(i) in column 2, after item 9, the following entry shall be inserted, namely :—

“(When granted on or before 1980);

(ii) in column 2, after item 9, the following entry shall be inserted, namely :—

“10. Diploma in Nursing Education and Administration”

[No. V. 14015/1(i)/81-PMS]

का.आ. 481.—भारतीय उपचर्या परिषद् ने, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसरण में 16 अप्रैल, 1983 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया है कि उसमें विनिर्दिष्ट की गई अर्हता, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता होगी;

और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय उपचर्या परिषद् की अधिसूचना संख्या 11-1/83 आई.एन.सी. नारीख, 27 जून, 1983 के साथ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है;

अत. अब, उक्त केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करसी है ताकि इसे उक्त घोषणा के अनुसार लाया जा सके, अर्थात्—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, भाग I में “क—सामान्य उपचर्या” परिषक के अन्तर्गत, क्रम संख्या 50 और उससे संबंधित प्रविधियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविधियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—

“51. केरल विश्वविद्यालय, विक्रम (जब 21 मार्च, 1972 को या उसके पश्चात् दी गई) ”

“52. पंजाब विश्वविद्यालय, अंडोगढ़ (जब 1 मार्च, 1977 को या उसके पश्चात् दी गई) ”

[संख्या वी.—14015/1/(II)/81-पी.एम.एस.]

S.O. 481.—Whereas the Indian Nursing Council has, by a resolution passed at a meeting held on the 16th April, 1983, in pursuance of sub-section (2) of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), declared that the qualification specified therein shall be a recognised qualification for the purpose of the said Act;

And, whereas the said resolution has been published in the Official Gazette with the notification of the Indian Nursing Council, No 11-1/83-INC, dated the 27th June, 1983, as required by sub-section (1) of section 15 of the said Act,

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, so as to bring it into accord with the said declaration, namely:—

In the Schedule to the said Act, in part I, under the Heading “A-Generic Nursing”, after serial number 50 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

- “51. University of Kerala, Trivandrum (when granted on or after the 21st March, 1972).
- 52. University of Punjab, Chandigarh (when granted on or after the 1st March, 1977). ”

[No. V 14015/1(H)/81-PMS]

का.आ. 482.—भारतीय उपचर्या परिषद् ने, उक्त अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 10 के अनुसरण में 27 मार्च, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषित करती है कि अब भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और सोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता की नीचे स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भान्यतापात्र अर्हताओं का नाम 15 सितम्बर, 1975 से इसके स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट नाम से बदल दिया जाए।—

(1)	(2)
सोक स्वास्थ्य उपचर्या में प्रमाण-पत्र	लोक स्वास्थ्य उपचर्या में डिप्लोमा।

अत. अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात्—

उक्त अनुसूची के भाग II में क्रम सं. 7 के सामने पंक्ति 2 में की प्रविधि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविधि रखी जाएगी, अर्थात्—

“सोक स्वास्थ्य उपचर्या में डिप्लोमा”।

(जब 15 सितम्बर, 1975 को या उसके पश्चात् दिया गया।)

[सं. वी.—14015/1(3)/81-पी.एम.एस.]

S.O. 482.—Whereas the Indian Nursing Council has, in pursuance of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), by a resolution passed at its meeting held on the 27th March, 1985, declared that the nomenclature of recognised qualification of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta specified in column (1) below be changed with effect from 15th September, 1975, to those specified in column (2) thereof :—

(1)	(2)
Certificate in Public Health Nursing	Diploma in Public Health Nursing

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby

makes the following amendments to the Schedule to the said Act, namely:—

In part II of the said Schedule, against serial number 7, in column 2, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Diploma in Public Health Nursing (when granted on or after the 15th September, 1975)".

[No. V. 14015/1/(iii)81-PMS]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1987

का.आ. 483.—दन्त-चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (ड) के अनुसरण में केरल राज्य सरकार द्वारा डा. जोस टी. मम्पिल्ली मंजूरी निदेशक आयुर्विज्ञान शिक्षा, त्रिवेंद्रम को 4 अगस्त 1987 से 8 अगस्त, 1988 तक डा. पी.आई. जॉन के स्थान पर भारतीय दृष्टि चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (ड) के अनुसरण में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 430 नामीख 24 जनवरी, 1984 का निम्नलिखित मंशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के परन्तुक के साथ पठित खण्ड (ड.) के अधीन नामांकित" शीर्षक के अधीन, अम संख्या 3 और उसमें मंवंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. डा. जोस टी. नामनिर्वाचित केरल सरकार मम्पिल्ली 4 अगस्त, 1987 से 8 अगस्त, 1988 तक"।

[संख्या वी-12013/2/87-पी.एम.एम.]

S.O. 483.—Whereas in pursuance of clause (e) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. Jose T. Mampilly, Joint Director of Medical Education Trivandrum has been nominated to be a member of the Dental Council of India by State Government of Kerala with effect from 4th August, 1987 to 8th August, 1988, vice Dr. P. I. John.

Now, therefore, in pursuance of clause (e) of section 3 read with sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 430 dated the 24th January, 1984 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (e) read with the proviso to section 3", for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"3. Dr. Jose Nominated Kerala 4th August  
T Mampilly Government 1987 to  
8th August,  
1988"

[No. V. 12013/2/87-PMS]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1987

का.आ. 484.—दृष्टि चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (क) के अनुसरण में डा. वी.आर. भुइया, प्रिसिपल, क्लेवीय दृष्टि चिकित्सा महाविद्यालय, गुवाहाटी, असम को 1 अगस्त, 1987 से असम राज्य सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद का सदस्य पुनः नामनिर्वाचित किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-3 के खण्ड (क) के अनुसरण में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.-430 नामीख 24 जनवरी, 1984 का निम्नलिखित मंशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के परन्तुक के साथ पठित खण्ड (क) के अन्तर्गत निर्वाचित" शीर्षक के अधीन, अम संख्या 2 के सामने स्तरम् 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1 अगस्त, 1987।"

[संख्या वी-12013/1/87-पी.एम.एम.]

जी जी. के. नायर, अवृत्त मन्त्रिव

New Delhi, the 22nd December, 1987

S.O. 484.—Whereas in pursuance of clause (e) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. B. R. Bhuyan Principal, Regional Dental College, Guahati, Assam has been re-nominated to be a member of the Dental Council of India by the State Government of Assam with effect from 1st August, 1987;

Now, therefore, in pursuance of clause (e) of section 3 read with sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 430 dated the 24th January, 1984 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (e) read with the proviso to section 3" against serial number 2, in column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"1st August, 1987."

[No. V. 12013/1/87-PMS]

G.G.K. NAIR, Under Secy.

नई दिल्ली 3 फरवरी, 1988

का.आ. 485.—परा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अनुसरण में डा. वी. रामलिङ्गमामी, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को (पद नाम से) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के स्थान में मनोनीत किया है,

और, यत्, डा. वी. रामलिङ्गमामी, महानिदेशक के मेवानियुत हो जाने के परिणामस्वरूप डा. पी.एम., पेटल ने

भारतीय आर्युक्तिज्ञान प्रनसंचान परिषद्, नई दिल्ली में महा-  
निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुभरण में केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 10 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 (सं. 5-13/59-एम.आई. दिनांक 9 जनवरी, 1960) में निम्नलिखित और संशोधन करती अर्थात् —

उक्त अधिनियम में, “धारा 3 की उपधारा (1) के बांड (इ.) के प्रत्यारूप मनोनीत” शीर्षक के नीचे अम संख्या 2 और उसमें संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

“2 डा. ए.एम. पेटल,

महानिदेशक,

भारतीय आर्युक्तिज्ञान प्रनसंचान परिषद्, नई दिल्ली (पद नाम से)“

[संख्या वी-11013/2/88-एम.ई. (पी)]

मर्वेश्वर आ, उप मंत्रिव

New Delhi, the 31st February, 1988

S.O. 485.—Whereas the Central Government has in pursuance of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), nominated Dr. V. Ramalingaswami, Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi (by designation) as a member of the Medical Council of India;

And whereas, consequent on the retirement of Dr. V. Ramalingaswami, Director General, Dr. A. S. Paintal has taken over as the Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health (No. 5-13/58-MI, dated the 9th January 1960) No. S.O. 138, namely:—

In the said notification, under the heading “Nominated under clause (e) of sub-section (1) of section 3, for serial number 2 and the entry relating thereto the following shall be substituted, namely:—

2 Dr. A. S. Paintal,

Director General,  
Indian Council of Medical Research,  
New Delhi (by designation).

[No. V. 11013/2/88-ME(P)  
SARWFISHWAR IHA, Dy Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1988

का.आ. 486.—गण्डीय विमानपत्रन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 64) के बांड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सर्वंशी के जे.एम. शेट्टी वित्त मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय

और राजन जेट्टर, राष्ट्र निदेशक, एयर इंडिया के स्थान पर जिनकी नियुक्तिया इस मंत्रालय की दिनांक 15 जून, 1987 की अधिसूचना संख्या प-11013/27/85-वी.ई.

(प.) द्वारा अधिसूचित की गई थी, के स्थान पर सर्वंशी पी.सी. मेम, संयुक्त मंत्रिव, नागर विमानन मंत्रालय और सी.एल. शर्मा, उप प्रबन्ध-निदेशक, एयर इंडिया को तत्काल में अंशकालिक मदम्य के स्पष्ट में नियुक्त करते हैं।

[संख्या प-11013/27/85-वी.ई. (एन.ए.ए.)]

जे.आर. नागपाल, अवर मंत्रिव

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th January, 1988

S.D. 486.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the National Airport Authority Act, 1985, (64 of 1985) the President is pleased to appoint S/Shri P. C. Sen, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation and C. L. Sharma, Deputy Managing Director, Air India as part-time members with immediate effect in place of S/Shri K.J.M. Shetty, Financial Adviser, Ministry of Civil Aviation and Rajan Jetley, Managing Director, Air India, respectively whose appointments were notified vide this Ministry's Notification No. A. 11013/27/85-VF(NAA), dated the 15th June, 1987.

[No. . 11013/27/85-VE(NAA)]

J. R. NAGPAL, Under Secy.

गण्डी विकास मंत्रालय

(संकरं प्रभाग डब्ल्यू 3)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1988

का.आ. 487.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदम्बली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की मारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे निदेश देनी है कि उक्त अधिकारी उक्त मारणी के स्तम्भ (2) में विनियिट सरकारी स्थानों की वाचन अपनी अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित करेंद्रियों का पालन करें।

मारणी

अधिकारी का पदनाम

सरकारी स्थानों के प्रबन्ध  
और अधिकारिता की  
स्थानीय सीमाएँ

1

- कर्तव्यालय इंजीनियर, “आर” दिल्ली और नई दिल्ली में प्रमाण केन्द्रीय लोक निर्माण उनकी अपनी अपनी विभाग, नई दिल्ली। अधिकारीद्वारा की स्थानीय

1	2	1	2
2. कार्यपालक इंजीनियर "ई" प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।	सीमाओं के भीतर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थान।	13. उप निदेशक, बागवानी उत्तरी प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।	
3. कार्यपालक इंजीनियर, संनिर्माण प्रभाग VI, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		14. उप निदेशक, बागवानी, दक्षिणी प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।	
4. कार्यपालक इंजीनियर, संनिर्माण प्रभाग VII, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		15. उप निदेशक, बागवानी, केन्द्रीय प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।	
5. कार्यपालक इंजीनियर, संनिर्माण प्रभाग XI, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।			
6. कार्यपालक इंजीनियर एशियाई खेल प्रभाग III, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		[फा. सं. 28012/87/87-जब्लू 3] एस. रंगनाथन, उपसचिव (संकरे)	
7. कार्यपालक इंजीनियर "ज" प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Works Division-W. 3)	
8. कार्यपालक इंजीनियर, डा. राम भनोहर लोहिया अस्पताल प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		New Delhi, the 6th February, 1988	
9. कार्यपालक इंजीनियर, सफदरजंग अस्पताल प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।		S.O.487:—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.	
10. कार्यपालक इंजीनियर, पुष्प विचार अनुरक्षण प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।			
11. उप निदेशक, बागवानी पूर्वी प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।			
12. उप निदेशक, बागवानी, पश्चिमी प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।			

## TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Executive Engineer, "R"	Premises under the administrative control of Central Works Department, New Public Works Department Delhi
2. Executive Engineer, "E"	Division, Central Public Works Department, New Delhi situated within local limits Delhi,
3. Executive Engineer, Construction Division VI,	of their respective jurisdiction in Delhi and New Delhi.
Central Public Works Department, New Delhi,	
4. Executive Engineer, Construction Division VII,	
Central Public Works Department, New Delhi.	
5. Executive Engineer, Construction Division XI,	
Central Public Works Department, New Delhi.	

- | 1   | 2 |
|---|---|
| 6. Executive Engineer,<br>Asian Games Division III,<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.                   |   |
| 7. Executive Engineer,<br>Division, Central Public<br>Works Department, New<br>Delhi.                                   |   |
| 8. Executive Engineer,<br>Dr. Ram Manohar Lohia<br>Hospital Division, Central<br>Public Works Department,<br>New Delhi. |   |
| 9. Executive Engineer, Saf-<br>darjung Hospital Division,<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.             |   |
| 10. Executive Engineer,<br>Pushp Vihar Mainten-<br>ance Division, Central<br>Public Works Department,<br>New Delhi.     |   |
| 11. Deputy Director of Hor-<br>ticulture, Eastern Division,<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.           |   |
| 12. Deputy Director of Hor-<br>ticulture, Western Division<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.            |   |
| 13. Deputy Director of Hor-<br>ticulture, Northern Division,<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.          |   |
| 14. Deputy Director of Hor-<br>ticulture, Southern Divi-<br>sion, Central Public Works<br>Department, New Delhi.        |   |
| 15. Deputy Director of Hor-<br>ticulture, Central Division,<br>Central Public Works<br>Department, New Delhi.           |   |

JF.No. 28012/87/87-W. 31  
S. RANGANATHAN, Dy. Secy. (Works)

जल भूतपूर्वक संवालय

(अम प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1988

का.आ. 488—बम्बई डाक कर्मचारी (रोजगार का विनियम) स्कीम 1956 में फिर मे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार डाक कर्मचारी (रोजगार का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक स्कीम का निम्नलिखित मसौदा प्रस्ता-वित करती है जिसे एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जैसी कि उक्त उप स्थान में अपेक्षा की गयी है। ऐसा उन सभी अधिकारियों की सूचना के लिए किया जाता है जिनकी कि इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा

नोटिस दिया जाता है कि इस प्रारूप पर इस अधिसूचना के सरकारी गजट मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के ममाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति मे उक्त प्रारूप के बारे मे उपर्युक्त अधिधि से पूर्व जो आपत्तियां और सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

#### स्कीम का प्रारूप

1. मंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इस स्कीम को बम्बई डाक कर्मचारी (रोजगार का विनियम) मंशोधन स्कीम 1988 कहा जा सकेगा।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से यह प्रवृत्त होगी।

3. बम्बई डाक कर्मचारी (रोजगार का विनियम) स्कीम 1956 मे।

(1) क्लाझ 16 के उप क्लाझ 2 मे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

- “(एन) गीयरमैन
- (ओ) गोदाम खलासी और
- (पी) कारपेटर”

(2) स्कीम की अनुसूची 1 की मद (2) मे निम्न-लिखित जोड़ा जाएगा :

- “(एन) गीयर मैन
- (ओ) गोदाम खलासी और
- (पी) कारपेटर”

[फा.सं. एस बी-13013/3/86-एल IV]

वी. शंकरलिङ्गम, निदेशक

#### MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

##### (Labour Division)

New Delhi, the 9th February, 1988

S.O. 488.—The following draft of a Scheme further to amend the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections/suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft before the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

#### DRAFT SCHEME

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Bombay Dock Workers Regulation of Employment Scheme, 1988.

2. It shall come into force from such date as may be notified by the Central Government.

**3. In Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 :**

(1) In sub-clause (2) of Clause 16, the following shall be added :

- (n) Gearman,
- (o) Godown Khalasi and
- (p) Carpenter."

(2) In item (2) of Schedule I of the Scheme, the following shall be added :

- (n) Gearman,
- (o) Godown Khalasi and
- (p) Carpenter."

[F. No. LB-13013]3/86-L. IV]

V. SANKARALINGAM, Director.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1988

का.आ. 489.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आदेश करते हैं कि संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय निम्नलिखित अधिकरणों पर श्रो एस.सी. सिन्हा, क्षेत्रीय प्रचार सहायक, क्षेत्रीय प्रचार यूनिट, रायबरेली के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उक्त नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट शक्तियों के अधिकारण के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए कार्य करेंगे—

- (1) यह कि उसने इस तथ्य की वह कोई सूचना जारी करने के लिए न सक्षम है न ही उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है और इस तथ्य की भी अवज्ञा करते हुए कि सूचना की अवधि पट्टानकार के खण्ड 15 के उल्लंघन में है, आजमगढ़ स्थित कार्यालय भवन की स्वामिनी श्रीमती उर्मिला मिश्रा, को नवम्बर, 1986 में यह सूचित करते हुए सूचना दी कि उक्त परिसर खाली कर दिया जायगा;
- (2) यह कि उसने श्रीमती मिश्रा का उक्त वास स्थान सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अनुमोदन अधिकारात् किए बिना खाली कर दिया;
- (3) यह कि श्रीमती उर्मिला मिश्रा के भवन को खाली करने के पश्चात् इस तथ्य की अवज्ञा करते हुए कि वह न तो नया वास स्थान किए पर लेने या उसे अधिभोग में लेने के लिए सक्षम है, न ही प्राधिकृत है, एक नए भवन में आजमगढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रचार यूनिट को रखने के लिए स्थानान्तरण कर लिया।

[फा. सं. गो-14013/2/87-मतरक्ता]

इन्दु भूषण कर्ण, अवर मन्त्रिव

**MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING**

**ORDER**

New Delhi, the 9th February, 1988

S.O. 489.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes a special order that the Joint Director, Directorate of Field Publicity, Madhya Pradesh—West Region, Bhopal, Ministry of Information and Broadcasting, shall act as the disciplinary authority for imposing any of the penalties specified in rule 11 of the said rules for the purpose of holding disciplinary proceedings against Shri S.C. Sinha, Field Publicity Assistant, Field Publicity Unit, Rai Bareilly, on the allegations that—

- (i) he issued a notice in November, 1986 to Smt. Urmila Misra, landlady of the office building at Azamgarh informing her that the said premises would be vacated by the office, ignoring the fact that he was neither competent nor authorised by the competent authority to issue such a notice as also the fact that the period of notice was in contravention of clause 15 of the lease agreement;
- (ii) he vacated the said accommodation belonging to Smt. Misra without obtaining prior approval of the competent authority.
- (iii) after vacating the building of Smt. Urmila Misra, shifted to a new building to house the Field Publicity Unit at Azamgarh, ignoring the fact that he was neither competent nor authorised to hire new accommodation or occupy it.

[File No. C-14013/2/87-Vig.]

I. B. KARAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1988

का.आ. 490 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, रेमेश पत्थर खदान वर्क्स, राजलवाडा, मुकाम और डाकधर राजलवाडा, तालुक मुगादिया, जिला भरुच के प्रबंध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के लिए, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकारण, अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-88 को प्राप्त हुआ था।

**MINISTRY OF LABOUR**

New Delhi, the 28th January, 1988

S.O. 490.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramesh Stone Quarry Works, At & P.O. Rajalwada, Taluka Jhagadia, Distt. Bharuch and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th January, 1988.

## ANNEXURE

BFOORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER,  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 16 of 1984

## ADJUDICATION

## BETWEEN

Ramesh Stone Quarry Works, At & P.O. Rajalwada,  
Taluka Jhagadia, Distt. Bharuch.

AND

The workmen employed under it.

In the matter of dearness allowance, special allowance, bonus, permanency and gratuity etc.

## AWARD

This industrial dispute between Ramesh Stone Quarry Works, At & P.O. Rajalwada, Taluka Jhagadia, Distt. Bharuch has been referred to me for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation No. L-29011/56/83-D.III(B) dated the 25th February, 1984.

2. The dispute relates to in all five demands regarding dearness allowance, special allowance, bonus, permanency, retaining allowance and gratuity etc.

3. It appears that soon after the reference was received, usual notices were issued to the Mahagujarat Khan Udyog Kamdar Sangh, Surat (hereinafter referred to as 'the Union') and Ramesh Stone Quarry Works, Rajalwada for filing their statement of claim and written statement respectively. However, the Rojnama shows that although the matter used to be adjourned from time to time in order to give sufficient opportunity to the Union to have his say in the matter the Union has never cared to remain present or even to file its statement of claim. It is clear from the record that this matter is pending from February, 1984 and more than three years have elapsed during which notices used to be issued to the Union. No useful purpose would be served by keeping this matter pending any further inasmuch as it is very clear that the Union is not interested in its demands. The demands are, therefore, rejected for want of prosecution and the reference stands dismissed. No order as to costs.

Ahmedabad,  
Dated, 21st December, 1987.

G. S. BAROT, Presiding Officer  
[No. L-29011/56/83-D.III(B)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

मई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

का.आ. 491:—दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्रीमती पी.एम. सिह के स्थान पर श्री आर.के. भाटिया, श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, विल्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम भंगालय की अधिसूचना

संख्या का.आ. 545 (अ) दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक नीचे मद 28 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:—

श्री आर.के. भाटिया,

श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

[संख्या यू-16012/2/88-एसएस-1]

New Delhi, the 29th January, 1988

S.O. 491.—Whereas the Delhi Administration has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri R. K. Bhatia, Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shrimati P. M. Singh;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 28 the following entry shall be substituted, namely:—

Shri R. K. Bhatia,  
Labour Commissioner,  
Delhi Administration, Delhi.

[No. U-16012/2/88-SS.1]

का.आ. 492:—राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री यु. महाबाला राव के स्थान पर श्री यामस.सी. जार्ज, विशेष सचिव, श्रम व पुनर्वाप विभाग, केरल सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम भंगालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 545 (अ) दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 16 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:—

श्री यामस सी.जोर्ज,  
विशेष सचिव श्रम एवं पुनर्वाप विभाग, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम  
[संख्या यू-16012/1/88-एस.एस-1]

S.O. 492.—Whereas the State Government of Kerala has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Thomas C. George, Special Secretary, Labour and Rehabilitation Department, Government of Kerala to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri U. Mahabala Rao;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely:—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 16, the following entry shall be substituted, namely :—

Shri Thomas C. George,  
Special Secretary,  
Labour and Rehabilitation Department,  
Government of Kerala.  
Trivandrum.

[No. U-16012/1/88-SS. I]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1988

का.आ. 493:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की अवसंध्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापना को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स केलटेक इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लि., 173, संगम नगर, इन्दौर।

2. मैसर्स ओसवाल एस्टेट प्रोसेसर्स 29/2, साउथ तुकोगंज, नाथ मन्दिर के समीप, इन्दौर-1;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(4)/88-स.सु.-2]

New Delhi, the 3rd February, 1988

S.O. 493.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Caltec Electronics (Private) Limited, 173, Sangam Nagar, Indore.

2. M/s. Oswal Estate Processors, 29/2, South Tukoganj Near Nath Mandir, Indore-1;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[No. S-35019(4)/88-SS-II]

का.आ. 494:—यतः मैसर्स रिसाइन्स एण्ड प्लास्टिक्स लिमिटेड, दोम चैम्बर, प्रथम मंजिल, 25 दलाल स्ट्रीट, बम्बई-400023, (इसके आगे जहां कही भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट को धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि साम उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है ;

प्रब्र इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की व्रदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्वर करेगा।

3. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सूचित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के ग्रन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेशेगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय, भविष्य निधि आपूर्कत की पूर्व

अनुमति के बारेर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित प्रबंधर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा और अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अधिकारी में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों का दुबारा लेखा परीक्षा कराएं और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के बर्बाद नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा एवं गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अधिधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा-परीक्षक द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर दुम्हा व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर धोतीय भविष्य निधि आयुक्त की प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों की आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निदेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभाव का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु व्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और व्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित व्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास बुकें, कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्वतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में व्याज उम दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड नियंत्रण करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित व्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ हैं तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की ओरी के कारण लूटखोट घ्यानत, गवन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियों प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की फैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अनग्र में लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी वाल के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की मेवा निवृत्ति होने के कानून्यरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है यह पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समष्टिहरण की दर आदि मंविधिक योजना के अन्तर्गत की गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्त द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्त, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रख-ग्रावर रिटैन प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "सम्बित मर्कार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तों लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्यनिधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों में स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने वाले भविष्यनिधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हो।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[मध्या एम-35012 (1) /88-पी. एफ.-II]

S.O. 494.—Whereas Messrs. Resins and Plastics Limited, Das Chancery 1st Floor, 25 Dalal Street, Bombay-400023 (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident

Funds Scheme 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the Provident Fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the Scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees [as defined in section 2(f) of the said Act] who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the General Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The Provident Fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipt into and payments from the Provident Fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or an officer authorised by him.

10. The account of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the Provident Fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Schedule Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and ensure timely realisation interest and redemption proceeds.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought up-to-date by the Board on presentation by the employees.

19. The account of each employee shall be credited interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such date may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft/burglary, Defalcation, misappropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribe from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contribution in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commission.

24. Notwithstanding anything contained in the Provident Fund rules of the establishment, if on the cessation of any individual, from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution, rate of forfeiture etc. under the Provident Fund rules of the establishment are less favourable as compared to those under the statutory scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of Provident Fund Contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35012(1)/88-SS-II]

का. आ. 495 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की वहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स रिलायन्स ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रैकल्स प्राइवेट लि., कोट शाऊस, तिलक मार्ग, धोबी तलाब, बम्बई-2
2. मैसर्स फिरोन्क सौदागर दरवेश एण्ड कम्पनी, 85-ए, सन्त साबता मार्ग, मुशतफा बाजार, पो. बा० नं. 6216, माझगांव, बम्बई-10
3. मैसर्स बैस्टर्न लम्बर्स, 85-ए, सन्त साबता मार्ग मुशतफा बाजार, पो. बा० नं. 6216, माझगांव, बम्बई-10
4. मैसर्स टीक वूड टिम्बर्स, 85-ए, सन्त साबता मार्ग, मुशतफा बाजार, बम्बई-10
5. मैसर्स मैट लैब सर्विसेज, प्राइवेट लि., 17 सी/ 18 शिवशंभु इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, एल बी एस मार्ग, थाटकोपर, बम्बई-86
6. मैसर्स गोल्डन रॉक शाऊस किपिंग एण्ड मरटीप्ल सर्विसिंग कम्पनी, 12 न्यू हैवन छेड़ नगर, बम्बई-89

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35018 (1)/88-स. सु.-2]  
ग. के भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 495.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishment, namely :—

1. M/s. Reliance Transport and Travels Private Limited Court House Tilak Marg, Dhobi Talao, Bombay-2.
2. M/s. Farouk Sodagar Darvesh and Company, 85-A, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, P.B. 6216, Mazagaon, Bombay-10.
3. M/s. Western Lumber 85-A, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, P. Box No. 6216, Mazagaon, Bombay-10.
4. M/s. Teak Wood Timbers, 85-A, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Bombay-10.
5. M/s. Met-Lab Services Private Limited, 17-C/18 Shivashakti Industrial Estate, L.B.S. Marg, Ghatkopar, Bombay-86.
6. M/s. Golden Rock House Keeping and Multiple Servicing Company, 12, New Haven Chheda Nagar, Bombay-89.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[No. S-35018(1)/88-SS-II]  
A. K. BHATTRAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

का. आ. 496 :—आंदोलिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, की मैसर्स भारत कोकिंग कॉल लि., की लोयाबाद कोलियरी के प्रवंशतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट आंदोलिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आंदोलिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20/1/88 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th January, 1988

S.O. 496.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Sijua Area and their workmen, which was received by the Central Government on 20-1-1988.

363 GI/88—8.

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 1 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Loyabad Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 15th January, 1988

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(67)/85-D.IV(B), dated the 17th/26th December, 1985.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Loyaband Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Sijua Area in dismissing from service Shri Baljore Passi, Driller w.e.f. 16-5-84 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

The case of the workman is that the concerned workman Shri Baljore Passi was a permanent driller of Loyabad Colliery. The management with an ulterior motive to victimise the concerned workman issued him a charge-sheet dated 24-3-84 on false and fictitious allegation. Although in the body of the charge-sheet it was not mentioned that the concerned workman was suspended from duty but practically he was not allowed to resume his duties. The concerned workman had represented before the management several times for allowing him to resume his duties but without any effect. Seeing no other alternative the concerned workman raised an industrial dispute on 29-10-83 challenging the illegal stoppage from work. Due to poverty and inhuman torture of the management the concerned workman lost his mental balance. He remained under the treatment of the doctor of Ranchi Mansik Arogyasala, Kanke, Ranchi. After recovery from illness the concerned workman reported for duty but the management instead of allowing him to resume duty handed over letter of dismissal dated 16-5-84 to him. The management dismissed the concerned workman illegally and arbitrarily after completing empty formalities. The alleged charge sheet dated 23-11-83 was never served on him. No notice of enquiry was issued or served on the concerned workman before conducting the domestic enquiry. The enquiry officer was in hot haste and completed exparte enquiry in one day. The finding of the enquiry officer in exparte enquiry was perverse being not based on the evidence on record. The concerned workman and the union represented before the management several times for reinstatement with full back wages but without any effect. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad and on failure of the conciliation the present reference was made to this Tribunal for adjudication. The action of the management in dismissing the concerned workman was not justified and the punishment of dismissal based against the concerned workman was too harsh and disproportionate of the alleged offence. The dismissal order against the concerned workman was passed

by an unauthorised person. On the above facts it has been prayed that the concerned workman be reinstated in the service from the date of his dismissal with back wages and other benefits.

The case of the management is that the concerned workman and his co-worker Sripat Chamar was on duty on 23-3-83 in the first shift duty in No. 5 Pit mine of Loyabud Colliery of BCCI. They refused to drill the wholes required for setting safari support. Thereafter they were issued with a charge sheet dated 24-3-83 for disobeying the lawful order of the superiors. They submitted the replies by their letters dated 31-3-83 and 18-4-83 admitting that they were ordered to drill Safari wholes but they refused to do so as the number of wholes required to be drilled by them were more than they could drill. They further stated that they were stopped from duties from 24-3-83. The concerned workman and his co-worker absented from the duties with effect from 24-3-83 with the object that the management would not ask them to drill Safari holes, and took several false pretext in the replies with the object of avoiding disciplinary action. The concerned workman and Sripat Chamar were issued warning letters dated 1-4-83 and 21-4-83 and were directed to join their duties immediately. Sripat Chamar resumed his duties with effect from 30-5-83 but the concerned workman did not join his duties and continued absenting from his duties. The concerned workman was issued with the charge sheet dated 20/23-11-83 for commission of misconduct of unauthorised absence from 24-3-83 without satisfactory cause and refusing to attend his duties in spite of letters issued to him from the management. The chargesheet was sent to the concerned workman by Regd. post but the concerned workman refused to accept the registered letter and the same was returned back. Again charge sheet was set by a registered post to him which appears to have been received by him as the same was not returned back. The concerned workman had refused to accept the charge sheet sent to him through Peon Book on 23-11-83. Shri S. Kumar, Sr. P.O. of Loyabud Colliery was appointed by a letter dated 29-11-83 as the Enquiry Officer to conduct the departmental enquiry into the charges against the concerned workman. The letter of enquiry was sent to the concerned workman through Peon Book on 1-12-83 but the concerned workman refused to accept the letter of enquiry and wrote to the Manager in a piece of paper that he should not be given any letter in future. The enquiry officer conducted the departmental enquiry on 5-12-83 ex parte against the concerned workman. The enquiry officer submitted his report holding the concerned workman guilty of the misconduct alleged against him. The enquiry proceeding, the enquiry report and all other relevant papers were duly examined at various levels and approval for dismissal of the concerned workman was obtained from the General Manager, C.M.E. of Area No. V and thereafter the concerned workman was dismissed vide letter dated 10-5-84 under the signature of the Supdt. of the Colliery who is the Agent under the Mines Act. The Supdt. and the Agent under the Mines Act and the G.M. are superior to the Agents and are either Additional Chief Mining Engineer or Chief Mining Engineer of the area concerned. The Supdt./Agents as well as the GM/Additional C.M.E/C.M.E. are competent authorities to dismiss the wage board employees. It is submitted on behalf of the management that the dismissal of the concerned workman is legal, bonafide and in accordance with the provisions of the Standing Orders and that the concerned workman is not entitled to any relief.

As the concerned workman has been dismissed from the service after holding a domestic enquiry into the charges against him, the management prayed that it first be decided as a preliminary point whether the domestic enquiry held into the charges against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principles of natural justice. So that in case it is held that the enquiry was not fair and proper, the management may get a chance to adduce evidence afresh before this Tribunal to establish the charges against the concerned workman. Accordingly the question whether the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper and in accordance with the principles of natural justice was taken up for hearing as a preliminary issue. Vide order dated 2-12-86

it was held that the ex parte enquiry held against the concerned workman holding him guilty of the charges was not fair, proper and in accordance with the principles of natural justice and the management was allowed to adduce evidence afresh before this Tribunal to establish the charges against the concerned workman.

Now the points for consideration are whether the management has been able to establish the charge against the concerned workman and whether the punishment of dismissal was too harsh and disproportionate to the charges established against the concerned workman.

The management examined four witnesses in all out of whom MW-1 was enquiry officer and had been examined at the time of the hearing of the preliminary issue. The documents of the management are marked Ext. M-1 to M-14. The workmen have examined the concerned workman Baljore Passi as WW-1 and have got two documents marked Ext. W-1 and W-2.

It will appear that formerly vide Ext. W-1 dated 24-3-83 the concerned workman along with Sripat Chamar were charge sheeted under clause 17(1)(c) and (i) of the Model Standing Orders. The workmen and his co-worker Sripat Chamar vide their explanation to the charge sheet Ext. M-2 admitted that they were in the first shift duty on 23-3-83 and that the work which was asked to be completed by them within eight hours duty was not possible for two workmen. Thereafter the management vide Ext. M-4 dt. 1-4-83 found that the explanation was not satisfactory and finding them guilty they were warned not to repeat such mistake in future and thereafter dropped the matter. It was also ordered that their work had not been stopped. It will thus appear that there was the end of the previous charge sheet dated 24-3-83 (Ext. M-1).

We are concerned with the charge sheet Ext. M-6 dated 20/23-11-83. It will appear from the charge sheet that the concerned workman was absenting since 24-3-84 without permission and without any satisfactory cause in spite of the fact that the management had asked them to join the duty. The concerned workman was, therefore, charge-sheeted under clause 17(1) (c) and (h) of the Model Standing Orders. Admittedly, the concerned workman did not file any explanation to the charge sheet dt. 20/23-11-83 Ext. M-6.

It is also admitted fact that the concerned workman did not attend his duty after 23-3-83. MW-2 Pashupati Singh is working as Sr. Overman in Loyabud Colliery. He has stated that the concerned workman along with Sripat Chamar were working under him as Drillman in March, 1983. It will appear from his evidence that on 23-3-83 in spite of his instruction to put Safari wholes the concerned workman and co-worker Sripat Chamar did not obey his order and they told that they would be doing only shot holes and will not be doing Safari holes. He has stated that he told them that if they do not do the work of Safari holes they should get the matter decided after meeting with the Manager. He has stated that they did no report for duty and absented. He has further stated that Sripat Chamar reported for duty on 30-5-83. The concerned workman remained absent. MW-4 Shri B. Ghosh is the Supdt of Loyabud Colliery since October, 1986 and prior to that he was working as Manager since 1982. He has stated that the concerned workman and Sripat were working as driller under him. He has further stated that the drillers working in the colliery drill holes on the face and also on the sides. It will appear from his evidence that the drillers are only to make holes for Safari supports for the safety of the mine and the drillers are not required to do the supporting. He has stated that supports are done by the timber gang. He has stated that on 23-3-83 the concerned workman and Sripat Chamar did not drill Safari holes and that in the evening of the day Pashupati Singh (MW-2) Overman-cum-Incharge reported to MW-4 that the concerned workman and Sripat refused to drill Safari holes. He has stated that on the next day he issued charge sheet on them and that the concerned workman and Sripat did not report for duty after the charge sheet. He has stated that he had issued the letters to the concerned workman and Sripat and thereafter Sripat joined his duty but the concerned workman did not join his duties. He has stated that thereafter he again issued charge sheet on the

concerned workman for his unauthorised absence and that an enquiry was held into the charges against the concerned workman and thereafter the concerned workman was dismissed from service vide Ext.M-14. In his cross-examination he has no doubt stated that there is certified standing orders in the colliery but it appears that he was not in know of the matter otherwise he would not have chargedsheeted the concerned workman previously under the Model Standing Orders. From the admitted facts and the evidence of MW-2 and MW-4 and also from the evidence of the concerned workman WW-1 it will appear that the concerned workman was absenting from duty with effect from 23-3-83, for over 10 days without any permission or authorised leave.

It is stated by the workman that the concerned workman got mental disease and as such he was under the treatment at Kanke Mansik Arogyasala. The workmen therefore have tried to explain the reason of the absence of the concerned workman. Let us examine whether the workmen have been able to establish that the concerned workman was unable to report for duty because of his mental disorder, during the period he had absented from duty. WW-1, the concerned workman, has stated that he got mental trouble after he had filed a petition before the AJC(C) for allowing him to resume duty. He has stated that he was treated at the mental hospital at Ranchi and Allahabad and after recovery he came to the colliery to join his duty but was not allowed to join and he was thereafter issued with a chargesheet for absence without leave. This evidence of the concerned workman shows that he was under the treatment at Mental hospital at Ranchi and Allahabad prior to the chargesheet issued to him for his absence without leave. In his cross-examination he has stated that with the same drill machine drillers make holes for Safari holes and shot holes and for the purpose of supporting there is another gang of timber man/Timber gang. He has stated that the Overman had told him to make the hole and to do the Timber supporting. But this evidence that he was asked to do the Timber supporting is belied vide Ext.M-2. Ext.M-2 shows that he refused to do more holes which was beyond their capacity and as such they did not get time for Safari holes. It appears therefore that after notice by the management there was no reason that the concerned workman should not have joined his duties when his other co-worker Sripat Chauri had joined his duties.

The concerned workman WW-1 has stated that he did not get any letter from the management to join his duty. He has stated that Sripat had joined after 2 months but as he had mental disorder, he did not join his duties. He has admitted that he had not filed any petition at the time when he had his mental disorder. He has stated that in Allahabad hospital he was an indoor patient but in Ranchi mental hospital he was an outdoor patient. He has stated that he has papers with him to show that he was being treated in the hospital at Allahabad as an indoor patient. He has stated that he does not possess the prescription of the Ranchi Hospital but he has certificate of his treatment from Ranchi Hospital with him at his residence. Inspite of this evidence the concerned workman has neither filed any certificate obtained by him from Swaroopnani Hospital at Allahabad or any certificate or any prescription from Ranchi Hospital to show that he was being treated in those hospitals for mental disorder. Moreover there is absolutely no evidence to show the period when he was being treated in the hospital at Allahabad or in the mental hospital at Ranchi. The burden lies heavy on the workman to establish satisfactorily about his absence if he has absented for more than 10 days without leave or permission. In the present case there is no document to show that the concerned workman had a mental disorder or that he was under the treatment for the mental disease at Allahabad or Ranchi. No other witness has been examined to show that the concerned workman was suffering from mental disorder for the period between 24-3-83 till the date of his dismissal 16-5-84.

WW-1 has stated in the last para of his deposition that he had received two chargesheets and had replied to the first chargesheet but had not replied to the second chargesheet. He has further stated that during the enquiry he had received the notice of enquiry but as he was severely

sick he could not attend the enquiry. MW-3 is the Peon Jalsi Sao who had gone with the letter to serve on the concerned workman. MW-3 has stated that he had taken Ext. M-4 for delivery to Baljore Passi. This Ext. M-4 is dated 1-4-83 by which the concerned workman was given warning in respect of chargesheet Ext. M-1. Ext. M-13 is the service report of the Peon MW-3. It will show that he had taken the letter No. 39/64 to the concerned workman which was refused to be taken by the concerned workman. The evidence of MW-3 along with the evidence of the concerned workman himself it will appear that the second chargesheet with which we are concerned in the present case was received by the concerned workman but even after that he did not give his explanation to the said chargesheet. It will also appear that the concerned workman had received the notice of enquiry but he did not attend. The reason given by him is that he was severely sick at that time. There is no evidence that the concerned workman was severely sick and it appears that the concerned workman was not being treated of his mental disorder at that time either at Allahabad or at Ranchi. It appears therefore that the explanation sought to be established by the workman regarding the absence of the concerned workman is not at all satisfactory and the said explanation cannot be accepted. I hold therefore that the concerned workman has failed to explain the admitted period of his absence.

It has been submitted that the punishment of dismissal of the concerned workman is too harsh and disproportionate of the alleged offence. It will appear from the facts of the case that the concerned workman had refused to do the Safari holes on 23-3-83 and he was chargedsheeted on 24-3-83 and he was absent from that very date without any application for leave. It is nowhere stated that the concerned workman had lost his mental balance from 24-3-83. If he had his mental balance on 24-3-83 there was no reason as to why he was absenting from 24-3-83 without permission or any authority. It is stated by the concerned workman that he had been stopped work by the Overman but there is absolutely no paper to show that the concerned workman had been stopped work from 24-3-83. The concerned workman had been dismissed with effect from 16-5-84. There is no petition of the workmen in between 24-3-83 and 16-5-84 by which the concerned workman had ever asked the management for leave or had informed the management regarding his mental disorder. In view of the lack of evidence it is not possible to hold that the concerned workman had absented due to his mental disorder for such a long period.

In the result, I hold that the action of the management of Loyaband Colliery of M/s. BCCL in dismissing the concerned workman Sri Baljore Passi from service with effect from 16-5-84 is justified and consequently he is entitled to no relief.

This is my Award,

I. N. SINHA, Presiding Officer  
[No. L-24012(67)/85-D.IV(B)]

का. आ. 497—आधिकारिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, व माध्यपुर कोलीयरी मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डज लि., के प्रबंधकाल में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आमनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20/1/88 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 497.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Asansol, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madhaipur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 20th January, 1988.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

Reference No. 2/87

PRESENT :

Shri G. P. Roy—Presiding Officer.

PARTIES :

The Employers in relation to the management of Madhai-pur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Nutardanga, Dist. Burdwan (W.B.),

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—None.

For the workman—None.

INDUSTRY : Coal

STATE : West Bengal

Dated, the 13th January, 1988

## AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(30)/87-D.IV (B) dated the 18th September, 1987.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Madhalpur Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Nutardanga, Dist. Burdwan (W.B.) in refusing Sk. Hiran, W/E Khalasi/Driver to resume his duties from 4-6-1985 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. The present Reference dated 18-9-87 was received from the Ministry by this Tribunal on 9-10-87. In the Reference the party raising the dispute viz. Colliery Mazdoor Sabha of India was asked to file statement of claim with relevant documents, lists of reliance and witnesses with this Tribunal within fifteen days of the receipt of the order of reference.

3. On receipt of the Reference it was registered as Case No. 2/87 in this Tribunal and Tribunal waited upto 23-10-87 for written statements etc. from the parties. But no such written statement was received from any of the parties. The next date was fixed on 13-11-87 when only the representative of the union appeared and prayed for time to file written statement and time was granted till 1-12-87 for the purpose. On that date the union again prayed for time and it was fixed on 15-12-87. On 15-12-87 none of the parties was present and no steps whatsoever were taken by any of the parties. Thereafter the case was fixed today i.e. 13-1-88 for hearing with fresh notice by regd. post to both the parties. From the record it appears that both the parties received the regd. notices. But none of them appeared today in this case.

4. In view of the above circumstances, it appears that neither the workman represented by the union nor the management is interested to proceed further in this case and accordingly it appears that no dispute between the parties exists.

5. In the circumstances, a 'no dispute' award is passed and the case is disposed of accordingly.

6. Requisite copies of the award are sent to the Ministry.

G. P. ROY, Presiding Officer  
[No. L-19012(30)/87-D.IV (B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

\* नई दिल्ली 3 फरवरी 1988

का. आ 498.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पुतकी कालयरी, मैसर्स भारत कॉकिं कोल लिमिटेड के प्रबन्धनन्त से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुवंश में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण, संख्या 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd February, 1988

S.O. 498.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pootkee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 19th January, 1988.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 284 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Pootkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. S. Bhattacharjee, Authorised representative of R.C.M.S.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 14th January, 1988

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012 (142)/86-D.III (A), dated, the 11th August, 1986.

## SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that the management of Pootkee Colliery of Bharat Coking Coal Ltd. should pay wages to their workman, Shri Kundan Singh, Tyndal for the period of his idleness, i.e. from the date of his previous superannuation in January 1981 to the date of his resumption of duty in December, 1981 is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

In this case none of the parties filed their respective W.S. etc. Both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise petition. I heard the parties on the said petition of compromise. I find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the said compromise petition which forms part of the Award as Appendix.

I. N. SINHA, Presiding Officer

## APPENDIX

In the matter of reference No 284/86

## PARTIES :

Employers in relation to the Management of Pootkee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Kusunda Dhanbad,

AND

Their Workmen.

Joint compromise petition of the Employers and Workmen

The above mentioned employers and workmen beg to submit jointly as follows :

1. That the employers and workmen have jointly negotiated the matter directly as covered by the aforesaid reference with a view to coming to mutually acceptable and amicable settlement.

2. That as a result of such direct negotiations, the parties have arrived at a settlement on the following terms :

- (a) That Shri Kundan Singh, Ex. Tyndal of Pootkee Colliery will be paid 50% of full wages for the entire period of his idleness. The wages will include basic, D.A., F.D.A. and V.D.A. and PR and UG allowance where applicable.
- (b) That he will also get the statutory bonus on the basis of the above payment.
- (c) That if he is still member of C.M.P.F. and his refund application is pending at colliery level, he will get the benefit of C.M.P.F.
- (d) That on fulfilment of the provisions referred to in clauses (a) and (b) above, the dispute referred to this Hon'ble Tribunal would stand finally resolved and that this Hon'ble Tribunal will be requested to pass an award accordingly.

In view of the above, the employers and the workmen most respectfully pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to dispose of the reference in terms of the joint compromise petition.

S. S. BHATTACHARJEE, Authorised representative  
of R.C.M.S.

For and on behalf of workmen,  
DHANBAD, dated,

B. M. LALL, Dy. Chief Personnel Manager,  
P. B. Area  
For and on behalf of employers  
[No. L-20012/142/86-D.III (A)]  
P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1988

का. आ. 499.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक आफ इडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd February, 1988

S.O. 499.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT  
AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 7 of 1980

## ADJUDICATION

## BETWEEN

Management of Union Bank of India Textile Market  
Branch, Surat First Party

AND

Their workmen

Second Party

In the matter of changing the system of allotment of work of Ledger Machine Operation from seniority basis to rotational basis.

## AWARD

This is a reference made by Government of India, Ministry of Labour, constituting Shri R. C. Israni as Presiding Officer of the Industrial Tribunal with headquarter at Ahmedabad, in exercise of the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference is made by the Central Government Order No. L-12011/30/79-D.II(A) dated 4-8-80 in respect of the dispute between the parties regarding changing the system of allotment of work of Ledger Machine Operation from seniority basis to rotational basis. By appropriate orders issued by the competent authorities the reference stands transferred to me.

2. The reference was fixed for hearing and before it could be heard and finally decided, Shri T. R. Mishra, President of Gujarat Mazdoor Panchayat for the Union has appeared today and made statement at the Bar that the dispute is resolved amicably and therefore inspite of intimations, no-one for the workman turned up. It is no use now adjourning the matter any more. The reference is therefore disposed of for non-prosecution. Shri B. K. Oza, Advocate for the Second Party is also present today in the Court. I, therefore, pass award accordingly. No order as to costs.

Ahmedabad,

Dated : 9-12-1987.

G. S. BAROT, Presiding Officer  
[No. L-12011/30/79-D.II (A) (Pt.)]  
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1988

का. आ. 500.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को एकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd February, 1988

S.O. 500.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govern-

ment Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Archaeological Survey of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th January, 1988.

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I. D. No. 197/83

In the matter of dispute between :

Shri Dharampal son of Shri Tek Chand, r/o House No.  
5392, Jampuri, Rewari, Haryana.

Versus

Management of Archaeological Survey of India, Janpath,  
New Delhi.

#### APPEARANCES :

Shri Narinder Chaudhary—for Management.

None—for workmen.

#### AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-42012(58)/82-D.II (B) dated 2-6-83 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Director, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi,

- (i) in refusing payment of wages to Shri Dharampal for the period from 26-9-81 to 29-1-1982 and
- (ii) in terminating the services of Shri Dharampal with effect from 27-2-1982 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The case of the workman is that he was initially appointed as skilled worker/clerk on daily wages in the Head Office of the Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi (hereinafter referred to as the Management) on 22-7-1980. On 26-9-81 when the workman was on duty in the Chemical Department and was actually applying chemical for maintenance and preservation of protected monuments namely Baradari of Roshanara Bagh he met with an accident which resulted in pelvis injury and rupture Urethra and fracture in left knee. He was removed to the Bara Hindu Rao Hospital where he was admitted and remained confined to bed for 124 days. None on behalf of the Management cared even to enquire about him after leaving him alone in the hospital nor gave him any salary/wages or monetary/medical aid or compensation during his long stay in the hospital and immediately 8-9 bottles of blood and other medicines were needed to save his life and his poor father spent about Rs. 5,000 by borrowing the same from his friends and relatives. The workman was discharged from the hospital and issued medical fitness certificate on 27-1-82 and he immediately reported for duty on the next day i.e. 28-1-82 and worked till 27-2-82. The Management terminated his services w.e.f. 28-2-82 by refusing him duty without any reasonable cause. The Management did not give him anything in writing except a character-cum-experience certificate issued on 8-4-82. It has been alleged that the termination of the workman constituted retrenchment and as the Management failed to comply with the pre-conditions of a valid retrenchment, the order of his termination is illegal and invalid and the workman claimed reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

3. The Management has not seriously disputed the working period as mentioned by the workman. Its case is that the workman was himself negligent in performing his duties and met with the accident because of his own mistake and the Management is not liable for any compensation. The workman and it was a case of forced absence on account of permanent nature and he was paid his daily wages for the days he performed his duties. After his discharge from the

hospital the workman was taken back on duty on 29-1-82 but he was not regular in his work and he was absent and whenever he was attending work he did so reluctantly and left the job earlier than the usual time and thereafter he could not be kept on the job due to no work.

4. MW-1 Shri R. K. Gangadhar Assistant Superintending, Archeological Chemist who appeared on behalf of the Management has stated that he cannot deny that the workman started working with the Management on 22-8-80. There is no dispute that the services of the workman were terminated on 28-2-82. It is also an admitted fact that the workman met with an accident at the work site and remained confined in the hospital from 26-9-81 to 25-1-82. The workman has placed on record the medical certificate Ex. W-1 and W 2 which go to show that the workman remained confined to the Hospital from 26-9-81 to 25-1-82 and he was declared fit to join duty from 28-1-82. It is, therefore, clear that it was not a case of voluntary absence from duty by the workman and it was a case of forced absence on account of sickness. Hence this period of absence from duty cannot be treated as break in service and consequently it stands established that the workman had put in continuous service with the Management from 22-8-80 to 27-2-82 and he had sailed into the protection of section 25-F of the I. D. Act. The Management has taken up contradictory stand because on the one hand it has been pleaded that after he resumed duty on return from the hospital the workman was not regular in his work and was absent and whenever he was attending the work he did so reluctantly and left job earlier than the usual time and on the other hand it was pleaded that he could not be kept on the job due to no work. The first plea indicates the alleged misconduct on the part of the workman and in that event the Management should have taken disciplinary action against him before terminating his services. But the Management did not serve any charge sheet or hold any enquiry against the workman. It is, therefore, clear case of retrenchment and the Management was under obligation to comply with the mandatory provisions of section 25-F of the I. D. Act. It is needless to say that even casual workmen are also entitled to the protection of section 25-F of the I. D. Act. Since the Management did not serve any notice on the workman nor paid him any wages in lieu of notice nor paid him any retrenchment compensation, the action of the Management in terminating his services w.e.f. 28-2-82 is clearly illegal and void. Hence the workman is entitled to reinstatement with continuity of service and full back wages from the date of his termination. As regards the non-payment of wages for the period from 26-9-81 to 29-1-82, when the workman was confined to bed in the hospital, the Management was quite justified in refusing wages for the period on the principle of "no work no pay" as the workman was employed only on casual basis and the proper remedy for the workman was to approach the appropriate authority under the Workman's Compensation Act. This reference stands disposed of accordingly.

15th December, 1987.

(G. S. KALRA)  
Presiding Officer  
Central Government Industrial Tribunal  
New Delhi

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : 15th December, 1987.

G. S. KALRA, Presiding Officer  
[No. L-42012(58)/82-D.II (B)]

का. आ. 501.—श्रीयोगिक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ई.एस. आई.सी. के प्रबंधतात्व से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट श्रीयोगिक विवाद में श्रीयोगिक अधिकारण, अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 501.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Ahmedabad, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of ESIC, Ahmedabad and their workmen which was received by the Central Government on 15th January, 1988.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL  
AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 13 of 1984

## BETWEEN

Employees' State Insurance Corporation Ahmedabad—  
First Party

AND

Their workmen —Second Party

In the matter of transfer of President, Vice President of  
ESIC staff Union and refusing promotion, etc.

## APPEARANCES :

Shri H. M. Shah—for the ESIC—First Party; and  
No one—for the Second Party.

## AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, constituting me as Presiding Officer of the Industrial Tribunal with headquarters at Ahmedabad, in exercise of the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. The reference is made by the Central Government Order No. L-15011(2)/83-D.IV dated 18-2-84, regarding transfer of President, Vice President of ESIC Staff Union and refusing promotion, etc. etc.

2. The ESIC Staff Union (hereinafter referred to as 'the union') has filed its statement of claim at Ex. 2. The Employees' State Insurance Corporation (hereinafter referred to as 'the ESIC') has filed its written statement at Ex. 6. The union has also filed additional statement of claim at Ex. 10 and the ESIC has filed its rejoinder at Ex. 11 and 14. From the Rojnama it appears that the union does not remain present. Shri A. K. Shah for the union appeared lastly on 30-6-86 and since then, from the Rojnama it appears that, the union has not remained present on the dates fixed for hearing on 25-7-86, 20-8-86, 12-9-86, 9-10-86, 27-10-86, 6-1-87, 3-3-87, 1-4-87, 29-4-87, 2-7-87, 4-8-87, 4-9-87, 6-10-87, 13-11-87 and 14-12-87. Two Registered letters were issued, one on 7-5-87 informing the union that the matter is peremptorily fixed for hearing on 2-7-87 and the other on 8-10-87 stating that the matter is once again peremptorily fixed for hearing on 13-11-87. But on both these dates and till today no one has appeared for the union though postal acknowledgements have been received duly signed and recorded at Exhs. 13 and 15 resp.

3. In view of the facts stated in the preceding para that inspite of two Registered notices duly served and even after the last date of peremptory hearing fixed on 13-11-87 the union has not cared to remain present or even sent any communication justifying its inability to remain present, the Court has no other alternative but to draw an adverse inference that the union is not interested in prosecuting the case any further. It is for the union to prove its case but it has failed to do so. In view of the above circumstances the reference is dismissed for want of prosecution and the demand is rejected consequently.

Ahmedabad,

Dated : 18-12-1987.

G. S. BAROT, Presiding Officer  
[No. L-15011/2/83-D.II (B)]

का आ. 502—ओद्योगिक विदाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आकाशवाणी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ओद्योगिक विदाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-1-88 को प्राप्त हुआ था।

[म. प्रम-42012/71/85-डी. [I (बी)]  
हरी सिंह, डेस्क अधिकारी

S.O. 502.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of All India Radio and their workmen, which was received by the Central Government on 19-1-1988.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I. D. No. 16/87

## In the matter of dispute between :

Shri Mangal s/o Badlu Singh, Peon, 33/318, Tilok Puri, Delhi-110091.

Versus

The Director, Doordarshan Akashvani Bhawan, New Delhi.

## APPEARANCES :

Shri C. P. Aggarwal—for the workman.

Shri Narinder Chaudhary—for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide Order No. L-42012/72-85-D.II (B) dated 18-2-87 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Doordarshan in terminating services of Shri Mangal Casual Labour from 31-10-84 is legal and justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. The case of the workman as revealed in the statement of claim is that he joined service with the Management as a Peon w.e.f. 12-7-81 on daily wages and he continued to work till 31-10-84 when his services were terminated without assigning any reasons. He has alleged that he was meted out with hostile discrimination as persons junior to him namely S/Shri Bhola, Madan, Satbir and Balwanand. Peons were retained in service and regularised whereas he was thrown out of the job. No notice was served upon him nor any wages in lieu of notice nor any retrenchment compensation was paid to him. He has alleged violation of section 25-F, G and H of the I. D. Act read with Rule 76 and 77 of the I. D. (Central) Rules 1957. Hence he has prayed for reinstatement with continuity of service and full back wages.

3. The Management in its written statement stated that the workman was engaged on casual basis and was not sponsored by the Employment Exchange as casual Labour for the period from 28-6-82 to 3-11-82 and from August, 1984 to November, 1984 and as such he could not be considered for regular employment and there was no discrimination. Since he was engaged on casual basis he was not eligible for any compensation. It was further stated that Doordarshan is not an Industry and is not governed by the provisions of the I. D. Act.

4. The workman himself appeared as WW-1 and submitted the documents Ex. W-1 to W-5. The Management did not produce any evidence although an affidavit of Shri G. K. Mohanty, Deputy Director Administration has been placed on record.

5. First of all the preliminary objection of the Management that Doordarshan is not an Industry and the provisions of the I. D. Act are not applicable to it is taken up. Doordarshan has all the attributes of an Industry as it meets the triple test of (i) Systematic Activity (ii) Organised by Co-operation between Employer and Employees and (iii) for the Production and or Distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes as laid down in the authority Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa and Others AIR 1978 SC 548. In fact it has been held time out of number that Doordarshan like AIR is an Industry and it does not behove the Management to raise this objection again and again.

6. As per the figures given by the Management itself, the workman had put in 265 working days during the 12 calendar months preceding the date of his termination and, therefore, he completed continuous service for one year as

defined in Section 25B of the I. D. Act and sailed into the protection of Section 25-F of the I. D. Act. As the Management has admittedly not served any notice nor paid any wages in lieu of notice nor paid any compensation to the workman there has been clear violation of the Mandatory provisions of section 25-F of the I. D. Act and the termination of the services of the workman clearly void and illegal and the workman is entitled to reinstatement with continuity of service and full back wages. This reference stands disposed of accordingly.

G. S. KALRA, Presiding Officer

Dated : 15th December, 1987.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

Dated : 15th December, 1987

[No. L 42012/72/85-D.II (B)]

HARI SINGH, Desk Officer